



04 - योगी कैबिनेट में बढ़ेगी आधी आबादी की हिस्सेदारी?



05 - जन प्रतिनिधित्व करते हैं ग्रामीण संवाददाता

A Daily News Magazine

इंदौर

गुरुवार, 23 अप्रैल, 2026



इंदौर एवं गोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 200, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रु. 2



06 - देश की 10 'सेफ सिटी' में ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में...



07 - किसानों की सुविधा के लिए उपार्जन केंद्रों में तैल कोटे 4 से बढ़ाकर 6...

कृषि

प्रसंगवश

अमेरिका अब तक ईरान को क्यों नहीं हरा पाया?

राजेश राजगोपालन

अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ जीत क्यों नहीं पा सके? ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बड़ी ताकतों छोटे विरोधियों से हार गईं। लेकिन यहां मध्य पूर्व में जो हो रहा है, वह पूरी तरह हाई-इंटेन्सिटी पारंपरिक युद्ध नहीं है। असल समस्या यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप इसे 'कम खर्च में जीतना' चाहते हैं। यह तब काम कर सकता था अगर लक्ष्य सीमित होता, जैसे पिछले साल ऑपरेशन मिडनाइट इहोर में हुआ था, या इस साल वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माद्रुरो को फंदा देने में। हो सकता है कि इन 'सस्ती जीतों' ने ट्रंप को ज्यादा आत्मविश्वास बना दिया हो।

इस बार उनका लक्ष्य बहुत बड़ा है: ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना। यह लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक ईरान की इस्लामी सरकार को नहीं हटाया जाता, और यह शायद बिना जमीनी आक्रमण के संभव नहीं है। इसके बजाय ट्रंप ने धमकियों का इस्तेमाल करके ईरान को परमाणु हथियार छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश की। लेकिन ऐसी धमकियां तभी काम करती हैं जब आपकी विश्वसनीयता हो, यानी आप यह दिखाएँ कि आप अपने लक्ष्य के लिए नुकसान सहने को तैयार हैं। ईरान ने दिखाया है कि वह दर्द सहने की क्षमता रखता है।

ईरान को हर क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है: उसकी वायुसेना, जो पहले ही बहुत मजबूत नहीं थी, काफी हद तक नष्ट हो गई है, उसकी नौसेना का बड़ा हिस्सा फारस की खाड़ी में डूब चुका है, और उसकी एयर डिफेंस प्रणाली भी बहुत कमजोर

हो गई है। उसके मिसाइल भंडार और नई मिसाइल बनाने की क्षमता के बड़े हिस्से भी नष्ट हो चुके हैं, हालांकि इन्हें फिर से बनाया जा सकता है।

सबसे गंभीर बात यह है कि उसके कई शीर्ष नेता मारे जा चुके हैं। समस्या यह है कि अमेरिका और इजराइल के सामने यह स्थिति है कि, इन सब के बावजूद, इस्लामिक शासन झुकने वाला नहीं है। अमेरिका के सामने एक बड़ी समस्या यह है कि वह उन दो चीजों को करने से रोका गया है जो वास्तव में काम कर सकती हैं। पहला है ईरान के तेल ढांचे को निशाना बनाना। एक तरफ, अमेरिका और उसके खाड़ी के सहयोगी इसे सही ठहरा सकते हैं क्योंकि ईरान पहले ही अपने पड़ोसी देशों के तेल उद्योग पर हमला कर चुका है। कतर, जो क्षेत्र में ईरान का सबसे करीबी दोस्त है, उसकी रास लाफान LNG संरचना पर हमला हुआ और उसे काफी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा, यह पूरी तरह अमेरिका और इजराइल की क्षमता में है कि वे ईरानी सुविधाओं पर हमला कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है, तो इसका कारण यह है कि ट्रंप तेल की कीमतों और उनके अमेरिकी शेयर बाजार पर असर को लेकर बहुत संवेदनशील रहे हैं। हालांकि वह बार-बार कहते हैं कि अमेरिका पर इसका कम असर होगा क्योंकि उसके पास पर्याप्त तेल और गैस है, लेकिन वह जानते हैं कि यह एक कमजोर तर्क है। अमेरिका वास्तव में तेल का शुद्ध निर्यातक है, लेकिन तेल बाजार एक ही ग्लोबल मार्केट बाजार है। जो कीमतों अमेरिका के उपभोक्ता देते हैं, वही दुनिया के बाकी उपभोक्ता भी देते हैं (स्थानीय टैक्स और अन्य शुल्क को छोड़कर)। इसलिए अगर वैश्विक स्तर पर तेल की

कीमत बढ़ती है, तो अमेरिका इससे बच नहीं सकता।

ईरानी तेल सुविधाओं पर हमला करने से यही प्रभाव होगा। यह भी एक कारण है कि अमेरिका ने रूसी और ईरानी तेल पर प्रतिबंध हटाए हैं, क्योंकि इन्हें ग्लोबल सप्लाई में जोड़ना कीमतों को कम रखने का एक तरीका है। अमेरिका ने इजराइल को भी ईरानी तेल ढांचे पर हमला करने से रोक दिया है।

डिस्टेंस के लिहाज से समस्या यह है कि ईरान जानता है कि यह ट्रंप की एक कमजोरी है और उसने इसका पूरा फायदा उठाया है। वह अपने पड़ोसियों पर हमला कर सकता है ताकि उन्हें अमेरिका का साथ देने की सजा दे सके, बिना किसी जवाबी कार्रवाई के डर के। इसके अलावा, तेहरान अपने पड़ोसियों को अमेरिका की बेबसी भी दिखा रहा है। यह ईरानी मनोबल और भविष्य की क्षेत्रीय स्थिति दोनों के लिए जरूरी है। इसलिए, तेहरान में बचा हुआ शासन जानता है कि अमेरिका की धमकियों की भी सीमाएं हैं।

एक और बड़ा डर, जिस पर ईरान भरोसा कर रहा है, वह है ट्रंप की यह अनिच्छा कि वे जमीनी सैनिक भेजें, ईरान पर ग्राउंड इनवेजन करें, या यहाँ तक कि फारस की खाड़ी में ईरानी द्वीपों पर सीमित हमला भी करें। यह पहले से साफ था, हालांकि न तो ट्रंप और न ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसे समझ पाए, कि ईरान के परमाणु हथियारों की महत्वाकांक्षा पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती जब तक ईरान की इस्लामी सरकार को हटाया न जाए।

उसके परमाणु ठिकानों का एक बड़ा हिस्सा नष्ट

कर दिया गया है, लेकिन पूरे कार्यक्रम को केवल हवाई हमलों या गुप्त ऑपरेशनों से खत्म नहीं किया जा सकता। इनसे कार्यक्रम की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन उसे जड़ से खत्म नहीं किया गया है। परमाणु हथियारों की कोशिश ईरानी शासन की रणनीति के अंदर गहराई से जुड़ी हुई है, और वे इसे अपनी खुद की अस्तित्व जितना ही महत्वपूर्ण मानते हैं।

यह शासन इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ देने को तैयार रहा है, जबकि यह एक तेल-समुद्र देश है जिसे ऐसी ऊर्जा तकनीक की जरूरत नहीं है। यह कहना कि ईरान सिर्फ अपनी तकनीकी संप्रभुता बचाना चाहता है या वह लंबे समय के भविष्य की तैयारी कर रहा है, हास्यास्पद बहाने हैं, क्योंकि शासन ने इसके लिए असमान रूप से बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो अंततः एक हथियार बनाने के लिए बनाया गया है।

अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम का 'घास कटान' की तरह नियंत्रित कर सकते हैं: यानी समय-समय पर हमला करके उसे फिर से बनाने या आगे बढ़ाने की कोशिशों को नष्ट कर सकते हैं। यह एक लंबी अवधि की प्रतिबद्धता है, जिसे अमेरिका खासकर शायद ही करेगा।

ईरान को बस कुछ साल इंतजार करना है जब अमेरिका में एक अधिक जोरिखम से बचने वाली सरकार आ जाए, और फिर वह अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को फिर से शुरू कर सकता है। अगर परमाणु हथियारों के कार्यक्रम को रोकना है तो शासन परिवर्तन जरूरी है। और यह कीमत ट्रंप देने को तैयार नहीं है।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

मोहन कैबिनेट ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा

जमीन अधिग्रहण पर अब मिलेगा चार गुना मुआवजा



भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कृषि भूमि के अधिग्रहण पर गुणन कारक (मल्टीप्लिकेशन फैक्टर) को दोगुना करते हुए 2.0 कर दिया गया है। इससे अब अधिग्रहित कृषि भूमि का मुआवजा किसानों को दोगुना के स्थान पर बाजार दर से 4 गुना प्राप्त होगा। यह निर्णय संपूर्ण प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि के अधिग्रहण पर लागू होगा। मंत्रि-परिषद ने नगरीय सीमा में मुआवजा गुणन कारक को यथावत एक रखा गया है। मंत्रि-परिषद ने इसके साथ सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसे अधोसंरचना निर्माण तथा विकास के कार्यों के लिए लगभग 33 हजार 985 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी है। कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए शेल्टर होम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। शेल्टर होम में मरीज के परिजनों को रकने और खाने की व्यवस्था सस्ती दरों पर मिल सकेगी। यह व्यवस्था निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में भी लागू होगी।

भू-अर्जन पर बाजार दर का 4 गुना मुआवजा मिलने से किसानों को होगा जबरदस्त फायदा

मंत्रि-परिषद ने किसानों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिफल और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गुणन कारक को बढ़ाकर 2.0 कर दिया गया है, जिससे किसानों को अब उनकी कृषि भूमि का बाजार दर से 4 गुना मुआवजा मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

इस निर्णय से सिंचाई परियोजनाओं, सड़क, पुल, रेलवे और बांध निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली कृषि भूमि पर किसानों को अधिक राशि मिल सकेगी। इससे न केवल विकास कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि भूमि देने वाले किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी व्यापक सुधार होगा। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में मंत्री श्री तुलसीराम सिलवाल, श्री राकेश सिंह और श्री चेतन्य कुमार काश्यप की उपस्थिति ने अनुशंसा की थी। उपस्थिति ने अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन करने के साथ ही विभिन्न किसान संगठन क्रेडिट, सीआईआई और फिक्की से चर्चा के बाद यह रिपोर्ट तैयार की थी।

छिन्दवाड़ा सिंचाई कामप्लेक्स परियोजना में पुनर्वास के लिए 969 करोड़ रुपये के विशेष पुनर्वास पैकेज की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा छिन्दवाड़ा सिंचाई कामप्लेक्स परियोजना में पुनर्वास के लिये स्वीकृत राशि 840 करोड़ 80 लाख रुपये के स्थान पर लगभग 969 करोड़ रुपये का विशेष पुनर्वास पैकेज स्वीकृति किया गया है। यह विशेष पैकेज त्वरित क्रियान्वयन व विस्थापितों के अपेक्षित सहयोग के लिए केन-बेतवा अन्तर्राज्यीय नदी जोड़ने परियोजना के समकक्ष प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है।

खाड़ी संकट ने बढ़ाई नई अनिश्चितता

ईरान-अमेरिका में 'बेपट्टी' वार्ता से बढ़ा संकट, एक्टिव सरकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान और अमेरिका के बीच पश्चिम एशिया में शांति को लेकर बातचीत फिलहाल फंस चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने एक तरफ एकतरफा सीजफायर बढ़ाने की बात कही है, वहीं तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ इलाके में अपनी मिलिट्री के 5,000 अतिरिक्त जवानों को भी उतारने वाले हैं। वहीं, ईरान ने भी होर्मुज में अपनी मुस्लेदी और बढ़ा दी है। ऐसे में फारस की खाड़ी में 28 फरवरी, 2026 के बाद से निकलने के इंतजार में खड़े रह गए भारतीय जहाजों के सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल के मुताबिक फारस की खाड़ी में इस समय अपने 14 जहाज मौजूद हैं। इनमें से 13 पर भारतीय झंडे लगे हैं और एक जहाज भारत के स्वामित्व वाला है, लेकिन किसी अन्य देश में रजिस्टर्ड (अन्य देश का झंडा) है।



भारतीय जहाजों की सुरक्षा पर लगातार नजर

अधिकारियों का कहना है कि फारस की खाड़ी में खड़े भारतीय जहाजों की सुरक्षा की स्थिति की व्यापक समीक्षा की गई है। इसके लिए भारत सरकार लगातार ईरानी सरकार के साथ संपर्क में है। यह समीक्षा शनिवार को दो भारतीय जहाजों पर ईरानी नौदी की ओर से हुई फायरिंग के बाद हुई है, जो होर्मुज जलडमरूमध्य से निकलने वाले थे। इससे पहले 10 भारतीय जहाज इस क्षेत्र से गुजर चुके हैं।

प्रोटोकॉल में सुधार की तत्काल जरूरत नहीं

बाद में इस घटना को लेकर यह बात सामने आई कि निशाना भारतीय जहाजों पर नहीं था और न ही इसके जरिए किसी बरू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। यह फायरिंग चेतावनी देने के लिए की गई थी। सोमवार को हुई इस समीक्षा के बाद कोई नई सुरक्षा एडवाइजरी जारी नहीं की गई है और मौजूदा दिशानिर्देशों का ही पालन किया जा रहा है। एक अधिकारी के अनुसार हालांकि, हालात बदल रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल में सुधार की तत्काल जरूरत नहीं है।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर जमकर गरजे लड़ाकू विमान

जगुआर, सुखोई, एम-17 और तेजस ने दिखाया अपना दम

सुल्तानपुर (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फिर भारतीय वायु सेना के विमान गरजे। एयरफोर्स के फाइटर विमानों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर विमान की टेकऑफ और लैंडिंग का अभ्यास किया। यह अभ्यास युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल जैसी परिस्थितियों में एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल करने की क्षमता को परखने के लिए आयोजित किया गया। दोपहर बाद एयर शो की शुरुआत हुई। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। एयर शो को लेकर मंगलवार को ही देश की सेना के जांबाज और फाइटर प्लेन सुल्तानपुर आए।



एयरफोर्स के आए नजर

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में बनी एयरस्ट्रिप पर सुखोई 30, जैगुआर, मिराज गरजते हुए टैक डाउन किया। इसके साथ ही वायुसेना के एमआई 17 हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्टर सी 295, एएन 32 भी देखने को मिले। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बने एयरस्ट्रिप की लंबाई करीब 3.2 किलोमीटर है। यहां एयरस्ट्रिप की सतह की मोटाई लगभग 320 मिलीमीटर है। यह सुखोई, मिराज-2000 और जैगुआर जैसे भारी लड़ाकू विमानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए पूरी तरह सक्षम है।

बिहार की सम्राट सरकार पर नीतिश की निगहबानी!

पटना (एजेंसी)। न्याय यात्रा, विकास यात्रा और समृद्धि यात्रा। इनके नाम पर जनता के मर्म को समझने और राज्य सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करने का सफर है। नीतिश कुमार अब अपनी यात्रा का क्या नाम देते हैं, यह पता नहीं। लेकिन, मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहते, यात्रा तो तय कर ही लिया। अब वे बिहार की जनता के प्रति 'तीसरी आंख' की भूमिका निभाएंगे। अब इसे नीतिश कुमार का सोशल अटैक कहें या वर्तमान सरकार की निगहबानी। मगर, इतना तो तय है कि वर्तमान सरकार को 'खुले सांड' की तरह नहीं छोड़ने वाले। बिहार के सियासी गलियारों में जब से बीजेपी के मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा शुरू हुई तब से उसके पैरलल नीतिश नीति पर

तीसरी आंख की रोल में रहेंगे सुशासन बाबू, करेंगे मूल्यांकन



चलेगी सरकार की भी चर्चा होती रही। न केवल नीतिश कुमार बल्कि उनके वरीय और कनीय नेता भी एक ही राग अलाप रहे थे कि मुख्यमंत्री बनने का मतलब ये नहीं कि बीजेपी कोई अपना एजेंडा चला दे। इसलिए, पंचायत से लेकर राजधानी तक में राज्य सरकार के क्रिया-कलाप पर नजर रखी जाएगी। नीतिश कुमार की यात्रा पर निकलने की जो

प्लानिंग बनी है, उसके पीछे का मकसद है कि बीजेपी कहीं अंदरूनी एजेंडे को राह देने में तो नहीं लगी। पिछले दिनों एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के शख्स की टोपी को अस्वीकार करने की घटना ने राज्य की सेक्युलर जनता को चौंकाया। टोपी लेना न लेना अपनी मर्जी है, मगर ये सरकार नीतिश कुमार के पद त्याग से बनी है। सम्राट चौधरी की इस हरकत के बाद एक अलग तरह का विवाद शुरू हो गया है। इस विवाद के साथ-साथ नीतिश का 'श्री सी' का कम्युनलिज्म प्रभावित होते दिखा।

राजस्व विभाग के फैसले पर भी सवाल!

जदयू सूत्रों की मानें तो राजस्व विभाग के एक विवादित फैसला भी नीतिश कुमार के संज्ञान में लाया गया है। हुआ ये कि सत्ता में आने के बाद सम्राट चौधरी ने राजस्व विभाग के एक पुराने फैसले को पलट दिया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे हड़बड़ी में लिया गया निर्णय बताया जा रहा है। सत्ता से बेदखल नीतिश कुमार जदयू की राजनीति को जनता के अंतिम पायदान तक पहुंचाने में जुटे हैं। साथ ही साथ जनता के बीच खुद की मौजूदगी दर्ज कराने यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान नीतिश कुमार धरातल पर चल रही योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का आंकलन करेंगे। साथ ही इन योजनाओं का प्रभाव की भी खोज-खबर लेंगे। लेकिन इन सबके साथ नीतिश कुमार ये संदेश भी जनता को देंगे कि जो कहां था सो किया यानि आपको छोड़ कर नहीं जा रहे हैं।



संक्षिप्त समाचार

नीतिश कुमार ने बनाई जेडीयू की नई टीम

राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 24 नेता, निशांत नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिश कुमार ने पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की है। इसमें उनके बेटे निशांत कुमार को जगह फिलहाल नहीं मिली है। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 24 नेताओं को रखा गया है। राज्यसभा सांसद संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे। वहीं, पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जहानाबाद से पूर्व सांसद चंद्रेश्वर



प्रसाद चंद्रवंशी को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। आलोक कुमार सुमन कोषाध्यक्ष होंगे। वहीं, 12 नेताओं को जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इसमें मनीष कुमार वर्मा, आपक अहमद खान, श्याम रजक, अशोक चौधरी, रमेश सिंह कुशवाहा, राम सेवक सिंह, कहकशां परवीन, कपिल हरिश्चंद्र पाटिल, राज सिंह मान, सुनील कुमार उर्फ इंजीनियर, हर्षवर्धन सिंह, मौलाना गुलाम रसूल और बलियावी का नाम शामिल है। राजीव रजन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने रहेंगे। वहीं, रविंद्र प्रसाद सिंह, विद्या सागर निषाद, दयानंद राय, संजय कुमार, मोहम्मद निसार, रूही तांगु और निवेदिता कुमारी को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है।

नेपाल में पीएम बालेन शाह की सरकार को बड़ा झटका

● गृहमंत्री सुदन गुरुंग ने भारी दबाव के बाद दिया इस्तीफा

काठमांडू (एजेंसी)। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब हाल के दिनों में व्यवसायी दीपक भट्टा के साथ उनके कथित व्यावसायिक संबंधों को लेकर विवाद सामने आए हैं। दीपक भट्टा पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जांच चल रही है। गुरुंग ने सोशल मीडिया के जरिए अपने इस्तीफे की घोषणा की।

शिवराज की अगुवाई में कृषि विकास को नई रफ्तार देने जा रहा है उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन

लखनऊ में 24 अप्रैल को जुटेगा उत्तर भारत का कृषि नेतृत्व

नई दिल्ली/लखनऊ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर 24 अप्रैल, शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित होने जा रहा उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन किसान-केंद्रित, परिणामोन्मुख और समन्वित कृषि विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सम्मेलन में उत्तर भारत के राज्यों के कृषि मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, वैज्ञानिकों, प्रगतिशील किसानों, एफपीओ, स्टार्टअप, केवीके, वित्तीय संस्थानों और खरीद एजेंसियों की भागीदारी के माध्यम से खेती, किसान आय, तकनीक, विपणन और कृषि अवसरचना से जुड़े मुद्दों पर ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आज कृषि भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर दिशा-निर्देश दिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र को अधिक आधुनिक, समावेशी और किसानोन्मुख बनाने के उद्देश्य से उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन 24 अप्रैल को लखनऊ में किया जा रहा है।

योगी बोले-ममता दीदी को रामनाम से चिढ़ है

लखनऊ (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी ने कहा- जब भारत आजाद हुआ तो तब पूरा देश रोजगार के लिए बंगाल आता था। उसके बाद पहले कांग्रेस ने लूटा, फिर कम्युनिस्टों ने नोचा, अब 15 साल से टीएमसी कंगाल कर रही है। सीएम ने कहा- बुआ-भतीजा मिलकर बंगाल के अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं। कोलकाता का मेयर कहता है यहां उर्दू चलेगी। मैं कहता हूँ कोई माई का लाल बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। बंगाल की पहचान काबा से नहीं मां काली बाड़ी से है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की जोरासांको और चक्रदहा विधानसभा सीट पर चुनावी रैली की। भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील करते हुए सीएम योगी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। रैली में एक बच्चा पोस्टर लेकर पहुंचा था जिस पर लिखा था- योगी जी बुलडोजर लाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सीएम योगी ने कहा- बंगाल में धड़ल्ले से गोहत्या होती है। भगवान राम के नाम से ममता दीदी को चिढ़ है। शोभायात्रा निकालने की परमिशन नहीं मिलती, टीएमसी के गुंडे गुंडा टैक्स वसूलते हैं। ऐसी स्थिति यूपी में भी थी सपा के गुंडों को टैक्स देना होता था। विकास ठप था, राम का नाम लेने वालों पर लाठी-गोली चलती थी। आज यूपी में उत्सव है। कहीं रामनवमी का उत्सव, कहीं कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव, कहीं कांवड़ यात्रा का उत्सव। यूपी में सब शांति है माफिया और गुंडा समाप्त है।

बंगाल की पहचान काबा नहीं मां काली से है

कोलकाता के मेयर कहते हैं-यहां तो उर्दू चलेगी



बेटी की इज्जत पर हाथ डालने वाला यमराज के घर जाता

सीएम योगी ने कहा- किसी बहन-बेटी की इज्जत पर हाथ डालता है तो सीधे यमराज के घर जाता है। अन्नदाता किसान खुशहाल है, विकास की बहार है और 500 साल में जो काम नहीं हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया है। इस बार बंगाल में डबल इंजन सरकार बनने जा रही है।

- रिजल्ट आते ही बंगाल फिर सोनार बांग्ला बनेगा- सीएम योगी ने कहा- यूपी में कब्जा नहीं होता। वहां गुंडा जानता है कि अगर कब्जा किया तो सरकार उनकी 7 पुरतों की जमीन निकालकर गरीबों के लिए घर बनवा देगी। मैं जानता हूँ 4 मई को जब रिजल्ट आया तो बंगाल सोनार बांग्ला बनके अपनी अस्मिता को पहचानेगा। उन्होंने कहा- हमें बंगाल की अस्मिता को बचाना। अभी जो कटमुल्लापन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसे हर हाल में रोकना होगा। इसके लिए भारत के लोकतंत्र ने जो ताकत दी है उसका इस्तेमाल कीजिए। सीएम योगी ने नादिया जिले की चक्रदहा सीट पर रैली की।
- बुलडोजर माफिया-गुंडों की हडिडियों का हाईवे बना देता- सीएम योगी ने कहा- यूपी में माफिया और गुंडा सिर उठाता है तो बुलडोजर उनकी हडिडी-पसली को हाईवे बनाने में उपयोग करता है। कांग्रेस और सपा के समय जो गुंडों ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किए उसमें गरीब की भूमि गरीब को दी। सरकार की जमीन सरकार के पास आई और उनकी खुद की कमाई से अर्जित जमीन पर गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। काशी, प्रयागराज में पूरी दुनिया आ रही है। ये तभी होता है जब भाजपा की डबल इंजन की सरकार होती है। हमने अयोध्या-काशी को संवारा है और बंगाल में गुरुदेव रविंद्र की पैतृक संपत्ति पर टीएमसी के गुंडों का कब्जा है।

ममता बनर्जी के कामों से खतरे में लोकतंत्र

बंगाल चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। आई-पैक पर हुई छपेमारी के समय ममता बनर्जी के प्रतीक जैन के घर में घुसने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप यूं ही बीच में दखल नहीं दे सकते हैं। उनके कामों से लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। आई-पैक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि वह अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति का काम है, जो मुख्यमंत्री भी हैं और जिन्होंने लोकतंत्र को खतरे में डालने के लिए पूरे सिस्टम का इस्तेमाल किया है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं और दो फेज में वोटिंग होनी है। इस



राजनैतिक मुद्दा बना था। केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया है कि बनर्जी ने उस जगह से अहम सबूत हटा दिए। कोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके कामों ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया।

राज्य और केंद्र के बीच का विवाद नहीं

हालांकि इस तर्क से असहमति जताते हुए जस्टिस कुमार ने कहा, इसमें राज्य का कौन-सा अधिकार शामिल है। यह राज्य और केंद्र सरकार के बीच का विवाद नहीं है। आप यूं ही बीच में दखल नहीं दे सकते। किसी भी राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री, किसी जांच या तपतीश के बीच में ही पहुंच जाता है, और आप कहते हैं कि यह असल में राज्य और केंद्र सरकार के बीच का विवाद है? उन्होंने पूछा, कोई भी मंत्री जांच के बीच में ही घला आता है और आप इसे लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हुए भी यह तर्क देते हैं कि यह मूलतः राज्य और केंद्र के बीच का विवाद है।

किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर कांग्रेस सेवादल का 24 घंटे का सत्याग्रह एवं उपवास आंदोलन

भोपाल। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशन में मध्यप्रदेश कांग्रेस सेवादल द्वारा किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर 24 घंटे का सत्याग्रह एवं उपवास आंदोलन आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम दिनांक 23 अप्रैल को प्रातः 11:30 बजे से प्रारंभ होकर 24 अप्रैल को प्रातः 11:30 बजे तक जवाहर भवन, रोशनपुरा, भोपाल में आयोजित होगा। कांग्रेस सेवादल द्वारा आयोजित इस सत्याग्रह का उद्देश्य प्रदेश के किसानों की समस्याओं-जैसे समर्थन मूल्य, फसल खरीदी में अनियमितता, भुगतान में देरी एवं प्रशासनिक उपेक्षा के खिलाफ आवाज बुलंद करना है। संगठन का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में किसानों को न्याय दिलाने के लिए लोकतांत्रिक और अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष आवश्यक है। इस आंदोलन में मध्यप्रदेश कांग्रेस सेवादल के तीनों विंग-सेवादल, महिला सेवादल एवं यंग ब्रिगेड सेवादल-के प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला अध्यक्ष अपने-अपने साथियों सहित बड़ी संख्या में सेवादल यूनिफॉर्म में भाग लेंगे।

लेंसकार्ट में तिलक विवाद

एमपी-यूपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में हुआ प्रदर्शन

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईवियर कंपनी लेंसकार्ट के ड्रेस कोड को लेकर विवाद बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग 4 दिनों से कई शहरों के लेंसकार्ट स्टोर में जाकर कर्मचारियों को तिलक लगा रहे और कलावा बांध रहे हैं। इस बीच बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने कंपनी के प्रमोटरर्स से कहा, 'तु अपनी कंपनी लाहौर में खोल ले, भारत में काहे को मार रहा है। तेरो कक्का का भारत है क्या, हं! हमारे तो बाप का भारत है।' पिछले सप्ताह सोशल मीडिया पर कंपनी का एक पॉलिस्सी डॉक्यूमेंट वायरल हुआ था। इसमें कर्मचारियों को बिंदी, तिलक और बुर्का पहनने पर रोक की बात थी। हिजाब और पगड़ी को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी। कंपनी के फाउंडर पीयूष बंसल ने 15 अप्रैल को एक्स पर पोस्ट कर बताया कि वायरल डॉक्यूमेंट पुराना है। यह कंपनी की मौजूदा गाइडलाइन नहीं दर्शाता। कंपनी सभी धर्मों का सम्मान करती है।



पाकिस्तान तो फेल रहा, भारत कर दिखाएगा

राजनाथ सिंह ने दिए ईरान-यूएस के बीच मध्यस्थता के संकेत

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान और अमेरिका के बीच 28 फरवरी से तनाव की स्थिति बनी हुई है। कई दिनों तक हुए हमलों के बाद दोनों देशों के बीच सीजफायर हुआ, लेकिन अभी तक शांति स्थापित नहीं हो सकी है। दोनों देश अपनी-अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने इस मध्यस्थता की कोशिश की है, लेकिन वह अभी तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका है। इस सबके बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बर्लिन में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कल ऐसा समय भी आ सकता है जब भारत अपनी भूमिका निभाए और इसमें सफलता भी हासिल करे। राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद से भारत के द्वारा मध्यस्थता की अटकलें तेज हो गई हैं। ईरान और अमेरिका के रिश्तों पर राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने कोशिश की है, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। हो सकता है कि कल ऐसा समय आए जब भारत इसमें अपनी भूमिका निभाए और सफलता भी हासिल करे।



हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों पक्षों से युद्ध समाप्त करने की अपील की है। कूटनीतिक मामलों में हमारे प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण बहुत संतुलित है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भी राजनाथ ने रखी बात

राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में व्यवधान कोई दूर की घटना नहीं बल्कि यह एक कड़वी सच्चाई है जिसका भारत की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर सीधा असर पड़ता है। उन्होंने जर्मनी की तीन दिवसीय यात्रा के पहले दिन रक्षा एवं सुरक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि आज दुनिया नए सुरक्षा खतरों का सामना कर रही है और तकनीकी परिवर्तन ने स्थिति को बेहद जटिल एवं परस्पर संबन्धित बना दिया है। बदलते परिवेश के अनुकूल ढलने की तत्परता के साथ एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जर्मनी यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब पश्चिम एशिया में 50 दिनों से अधिक समय से संघर्ष जारी है और इसके परिणाम सामने आ रहे हैं।

ईवीएम पर गोंद, परफ्यूम लगाने वालों को छोड़ेंगे नहीं

बंगाल-तमिलनाडु चुनाव से पहले चुनाव आयोग की चेतावनी, वोटिंग आज

नई दिल्ली (एजेंसी)। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ईवीएम के बटन पर इत्र, गोंद या किसी भी तरह का पदार्थ लगाना छेड़छाड़ माना जाएगा और यह चुनावी अपराध है। हाल के दिनों में यह दावा सामने आया था कि कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता यह पता लगाने के लिए ऐसा करते हैं कि वोट उनके पक्ष में पड़ा है या नहीं। मंगलवार को अधिकारियों ने कहा कि अगर किसी मतदान केंद्र पर ऐसी कोई हस्तक सामने आती है, तो वहां के पीठासीन अधिकारी को तुरंत सेक्टर अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी को इसकी जानकारी देनी होगी। यह निर्देश तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कल 23 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले दिए गए हैं। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसे मामलों में आयोग सख्त कार्रवाई करेगा और जरूरत पड़ने पर दोबारा मतदान (री-पोल) का आदेश भी दिया जा सकता है।



बटन पर कुछ भी लगाना सख्त मना

अधिकारियों ने सभी मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ईवीएम के सभी उम्मीदवारों के बटन साफ और स्पष्ट दिखाई दें। किसी भी बटन पर टैप, गोंद या अन्य कोई चीज नहीं लगी होनी चाहिए। उन्होंने यह भी साफ किया कि बैलेट यूनिट के बटन पर किसी भी तरह का रंग, स्याही, इत्र या रसायन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इससे वोट की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है। अगर इस तरह की कोई हड़बडी पाई जाती है, तो पीठासीन अधिकारी तुरंत उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दें।

पहलगाम हमले के एक साल, दुनिया भर से निंदा

● यूरोप के 27 देश और ईयू आर भारत के साथ, बोले-भूलेंगे नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में बीते साल 22 अप्रैल को भीषण आतंकी हमला हुआ था। पाकिस्तान से आए आतंकीयों ने चुन-चुन कर उन लोगों को मार डाला था, जो हिंदू थे।



उनका धर्म और नाम पूछकर यह कत्लेआम किया गया था। आज इस घटना को एक साल हो गए हैं और दुनिया भर में इसकी निंदा की जा रही है। इस बीच यूरोपियन यूनियन और उसके 27 सदस्य देशों ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। बुधवार को यूरोपियन यूनियन की ओर से एक पोस्ट किया गया।

तीन राज्यों में कितनी सीट पाएगी कांग्रेस, शाह ने बताया!

● गृहमंत्री की बड़ी भविष्यवाणी, एक में तो जीरो का अनुमान

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। बंगाल की सत्ता पर काबिज होने का दावा करने वाली भाजपा के नेता ने कहा कि मैं राहुल गांधी को बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस यहां खाता भी नहीं खोल पाएगी। दमदम में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं राहुल गांधी को बता दूँ कि बंगाल में



कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सकेगा। इसके अलावा उन्होंने दो और राज्यों तमिलनाडु और पुदुचेरी को लेकर भी कांग्रेस के बारे में भविष्यवाणी की। अमित शाह ने कहा कि पुदुचेरी और तमिलनाडु में कांग्रेस का आंकड़ा दहाई तक नहीं पहुंचेगा

यानी वह 10 या उससे ज्यादा सीटें नहीं हासिल कर सकेगी। बंगाल के दमदम में अमित शाह ने वोटर्स से देश के नाम वोट करने करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप लोग अपना वोट घुसपैठिया मुक्त बंगाल के लिए करें।

अग्नि सुरक्षा की अनदेखी, दो रेस्टोरेंट सील



इंदौर। जिले में अग्नि सुरक्षा प्रबंधों को लेकर सचन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले भवनों एवं संस्थानों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में मंगलवार को पीयू-3 स्कीम नंबर-54 के भूखंड क्रमांक 13-14 एवं 32-33 पर स्थित भवनों में बड़ी कार्रवाई की गई। यहां रूफटॉप पर संचालित कबौला वेज बारबेक्यू एवं एयरन हाइट रेस्टोरेंट एंड किचन में अग्नि सुरक्षा से संबंधित आवश्यक उपकरण नहीं पाए गए। साथ ही बिना स्वीकृति के किचन संचालन भी किया जा रहा था। इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए प्रशासन द्वारा दोनों रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। यह कार्रवाई तहसीलदार मल्हारराज निधि धाकड़, भवन अधिकारी जेन-07 टीना सिसोदिया, भवन निरीक्षक पीयूष मावी एवं राजस्व टीम की उपस्थिति में संपन्न हुई। जिले में हिदायत दी गई है कि अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे संस्थानों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

आरटीओ धार ने चेकिंग अभियान चलाया



धार। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, धार एवं उनकी टीम ने 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक संयुक्त रूप से विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान पाया गया कि जिले के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के वाहनों (बस, ट्रक, डंपर, पिकअप, स्कूल बस) द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए वाहन स्वामियों द्वारा जानबूझकर बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना पीयूषी एवं नियम विरुद्ध वाहनों का संचालन किया जा रहा था। जिस पर सख्ती से कार्यवाही की गई। जांच के दौरान नियमों के विरुद्ध संचालित पाए गए वाहनों से 2,37,000 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया एवं 2 जन्त वाहनों से लगभग 1 लाख 50 हजार की वसूली की गई। वाहनों का नियम विरुद्ध संचालन पाए जाने पर इस प्रकार की चालानी कार्यवाही की जाएगी। परिवहन विभाग धार द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर निरंतर चेकिंग कार्यवाही की जाती तथा नियम उल्लंघन पाए जाने पर वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्यवाही की जाती है।

ब्राह्मण परिवार को मांसाहारी भोजन परोसा

इंदौर। ब्राह्मण समाज का युवक और दो युवतियां खाना खाने केफे पर गए। वहां वेटर ने उन्हें मांसाहारी भोजन परोस दिया, जबकि युवक ने शाकाहारी डिश का आर्डर किया था। मांसाहारी भोजन परोसने के बाद विवाद हो गया। मामले में युवक ने तुकोगंज थाने पर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। युवक अमोल पिता बारकू पाटकर निवासी नालदा परिसर ने बताया कि वह 18 अप्रैल को रात पौने 10 बजे अपनी महिला मित्र अदिति मोटानी और डिंपल शुक्ला के साथ 'कैफे मामा लोक' पहुंचा था। यहां युवक ने ओनियन रिंग का आर्डर किया। कुछ देर बाद वेटर ने चिकन विंसेस परोस दिया। जब युवक ने डिंस खाई तो उसे शंका हुई। वेटर से पूछने पर पता चला कि डिंस मांसाहारी है। युवक मांसाहारी भोजन का फोटो, वीडियो करता, इसके पहले ही वेटर ने प्लेट को वाशरूम में रख दी। जब कैफे मालिक से शिकायत तो वह अभद्रता करने लगा। घटना से क्षुब्ध युवक आर्डर का बिल चुकाने बगैर कैफे से बाहर आया और पूरे मामले की शिकायत की। मामले में टीआई जितेंद्र सिंह यादव ने बताया कि जांच के बाद मैनेजर और मालिक पर कार्रवाई की जाएगी।

बेहतर काम का 23 पुलिस वालों को इनाम

इंदौर। पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को हैसला अफजाई करने उन्हें बेहतर काम का इनाम भी दिया जाता है। इसी क्रम में चारों जेन के 23 अधिकारियों, कर्मचारियों को नकद राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में उपनिरीक्षक विकास यादव, प्रदीप यादव, कार्यवाहक सहायक उपनिरीक्षक महेंद्र सिंह चौहान, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक शाशांक दुबे, आरक्षक पंकज चौहान, गौरव गुर्जर, रामवीर गुर्जर थाना राजेंद्र नगर को अंधे कल्ल का पदार्पण करने, कार्यवाहक उपनिरीक्षक अनिल गौतम, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक पंकज सांवरिया, आरक्षक जबर सिंह थाना खजुराना को 100 ग्राम एमडी ड्रस, आरक्षक घनश्याम, शामू सिंह थाना संयोगितागंज को वाहन चोरी की वारदात का खुलासा करने, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक बलराम, आरक्षक धीरज पांडे, अनिल मकवाना, सुनिल सोनी थाना चंदन नगर को 3 तस्करों को पकड़ने के लिए पुरस्कार दिया। इसी प्रकार, महिला आरक्षक नेहा को रेडीसन आउटर पॉइंट चौराहे पर बेहतर यातायात प्रबंधन करने, बसु चौहान को नृसिंह बाजार चौराहे पर यातायात प्रबंधन करने, कार्यवाहक सहायक उपनिरीक्षक अमृत गोखले, आरक्षक खूबसिंह धाकड़ को शराब परिवहन करने वाले ट्रक को पकड़ने, उपनिरीक्षक फतेह सिंह आंजना, कार्यवाहक सहायक उपनिरीक्षक सतेंद्र सिंह जादवी, आरक्षक संजय बरोड को 121 ग्राम एमडी जन्त करने पर इनाम दिया गया।

टकर से युवक की मौत, पुलिस जांच

इंदौर। शहर में एक ओर हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां नेमावर रोड पर सड़क पार करते समय युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान दिलीप (42) निवासी पालदा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, सोमवार रात करीब 11 बजे हुए इस हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वाहन संभवतः आयरथ था, जिसने तेज रफ्तार में व्यक्ति को टक्कर मारी। स्थानीय लोगों ने घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। मृतक के पास से मिली डायरी और टूटे हुए मोबाइल के आधार पर पहचान की कोशिश की गई, हालांकि शुरुआती समय में कोई पुष्टि नहीं हो सकी। भंवरकुआं थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार वाहन व चालक की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खाले जा रहे हैं। वहीं, पुलिस मृतक के परिजनों तक सूचना पहुंचाने के प्रयास भी कर रही है।

लोक निर्माण विभाग के 3 अफसरों को लोकायुक्त ने रिश्त लेते पकड़ा

इंदौर। मंगलवार को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के तीन अधिकारियों को रिश्त लेते हुए लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। इस कार्रवाई में कार्यपालन यंत्री जयदेव गौतम, अनुविभागीय अधिकारी टीके जैन और उपयंत्री अंशु दुबे शामिल हैं। तीनों पर एक ठेकेदार से अंतिम भुगतान के बदले मोटी रकम मांगने का आरोप है। लोकायुक्त दल ने जयदेव गौतम को उनके शासकीय निवास से 1 लाख 50 हजार रुपए लेते हुए पकड़ा, जबकि टीके जैन को कार्यालय परिसर के पोर्च के नीचे 1 लाख रुपए लेते समय गिरफ्तार किया गया। अंशु दुबे ने भी 1 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन पूरी रकम उपलब्ध नहीं होने के कारण उसने पैसे नहीं लिए। इस कार्रवाई में कुल 2 लाख 50 हजार रुपए जन्त किए गए।

साढ़े 3 लाख की रिश्त मांगी

मामला धार निवासी ठेकेदार राजपाल सिंह पंवार से जुड़ा है, जो पटेल इंटरप्राइजेज के संचालक हैं। उनकी फर्म ने वर्ष 2023 में मैथवाड़ा फोरलेन पहुंच मार्ग का काम 4 करोड़ 73 लाख रुपए में लिया था और इसे 4

बिल पास करने के बदले मांगे साढ़े 3 लाख रु, नकदी बरामद



जाल बिछाकर कार्रवाई

इसकी शिकायत ठेकेदार ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में की। जांच में आरोप सही पाए जाने पर मंगलवार को जाल बिछाकर कार्रवाई की गई और तीनों अधिकारियों को पकड़ा गया। आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में निरीक्षक आशुतोष मिठास, प्रतिभा तोमर और विवेक मिश्रा सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। पूरी कार्रवाई लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख और उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज कुमार सिंह के निदेशन में की गई।

करोड़ 51 लाख रुपए में पूरा किया। काम पूरा अधिकारियों ने 3 लाख 50 हजार रुपए की होने के बाद अंतिम बिल के भुगतान के लिए रिश्त की मांग की थी।

मांगलिया डिपो के सामने भीषण

आग, हड़कंप, तीन घंटे में काबू

यहां स्थित तेल डिपो में हजारों लीटर पेट्रोल और डीजल

इंदौर। क्षिप्रा थाना अंतर्गत मांगलिया क्षेत्र में मंगलवार दोपहर सवा तीन बजे बड़ी आगजनी की घटना ने पूरे इलाके में अफसर-तफरी मचा दी। मांगलिया स्थित तेल डिपो के ठीक सामने सात्विक विहार के पास अटाला दुकान में अचानक आग भड़क उठी, जिसने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया था। शार्ट सर्किट से लगी आग की लपटें इतनी तेज और ऊंची थी कि उन्हें दूर-दूर से देखा जा सकता था। देखते ही देखते आग ने आसपास की दुकानों और कुछ मकानों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यहां स्थित तेल डिपो में हजारों लीटर पेट्रोल और डीजल का भंडारण रहता है। ऐसे में आग के और अधिक फैलने का खतरा बना हुआ है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और दमकल विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया था। आग के बाद से लगातार फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन आग की तीव्रता के कारण इसे काबू में लाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ था।

सभी रास्तों को बंद किया

सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने डिपो के आसपास के सभी रास्तों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। मुख्य मार्ग पर यातायात रोक दिया गया है, जिससे लंबा जाम लग गया है। वहीं, तेल से भरे टैंकों को भी डिपो के बाहर ही रोक दिया गया था, ताकि किसी भी प्रकार का बड़ा हादसा टाला जा सके। पुलिस और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था। एहतियात के तौर पर पूरे इलाके को खाली कराया गया था। राहत की बात यह है कि हादसे में किसी प्रकार जनहानि नहीं हुई।

ई-रिक्शा व्यवस्था को मिला नया रंग शुरू हुई कलर कोड सेक्टर प्रणाली

इससे ई-रिक्शाओं की पहचान और उनका संचालन आसान होगा

इंदौर। शहर में यातायात को और अधिक व्यवस्थित बनाने पुलिस ने नई पहल की है। 21 अप्रैल को पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में ई-रिक्शा संचालन के लिए कलर कोड सेक्टर व्यवस्था की शुरुआत की गई। इस नई व्यवस्था के तहत शहर को 4 जेन में बांटा गया है और हर जेन को एक अलग रंग दिया गया है। जेन 1 के लिए नीला, जेन 2 के लिए पीला, जेन 3 के लिए लाल और जेन 4 के लिए सफेद रंग निर्धारित किया गया है। इससे ई-रिक्शाओं की पहचान और उनका संचालन आसान होगा।



एक क्षेत्र में नहीं होगी भीड़

ई-रिक्शा का सेक्टर आवंटन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर किया जा रहा है। साथ ही, जिन लोगों के पास एक से ज्यादा ई-रिक्शा हैं, उनके वाहनों को अलग-अलग जेन में बांटा जाएगा, ताकि किसी एक क्षेत्र में भीड़ न बढ़े। पंजीकरण के लिए तय फॉर्म भी जारी किया गया है, जिसके जरिए अब तक 6000 से ज्यादा ई-रिक्शा चालकों का रजिस्ट्रेशन पूरा किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि इस पहल से शहर में यातायात व्यवस्था और बेहतर होगी। साथ ही, ई-रिक्शा चालकों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में सहयोग दें।

पूर्व महिला बैंक प्रबंधक ने गंभीर आरोप लगाए, अफसरों के खिलाफ शिकायत

जनसुनवाई में पहुंची पीड़िता, निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की

भविष्य खराब करने की धमकी

पीड़िता ने आरोप लगाया कि श्रम कार्यालय के बाहर उन्हें खुलेआम धमकी दी गई कि उनका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें भोपाल और जबलपुर के चक्रर लगाकर मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, ताकि वे शिकायत वापस ले लें। उन्होंने बताया कि नौकरी के दौरान डर के कारण वह चुप रही, क्योंकि उन्हें वेतन रोकने और भविष्य खराब करने की धमकी मिलती थी। अब शासन की महिला सुरक्षा व्यवस्था और 'शी-बॉक्स' पोर्टल से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी बात सामने रखी है।

दी जाती थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अनिवाय अवकाश तक नहीं दिए जाते थे।

नौकरी से इस्तीफा दिया

स्थिति से परेशान होकर निहारिका ने इस्तीफा दे दिया और तीन महीने की नोटिस अवधि भी पूरी की।

लेकिन, इस दौरान भी मानसिक दबाव बना रहा। उनका कहना है कि बकाया प्रोत्साहन राशि मांगने पर क्षेत्रीय और जेनल स्तर के अधिकारियों ने भुगतान रोक दिया। श्रम अधिकारी के समक्ष शिकायत करने पर भी बैंक पक्ष के लोग मध्यस्थता बैठक में शामिल नहीं हुए।

'वंदे मातरम् विवाद' पर इंदौर कांग्रेस में हलचल, नेताओं को देवास बुलाया

अनुशासन समिति ने सवाल पूछे, बयानबाजी पर सफाई मांगी

इंदौर। नगर निगम परिषद की बैठक में हुए वंदे मातरम् विवाद के बाद कांग्रेस संगठन में हलचल तेज हो गई है। मामले को गंभीर मानते हुए अनुशासन समिति ने बुधवार को इंदौर के सभी कांग्रेसी नेताओं और मुस्लिम पार्षदों को देवास तलब किया। बैठक में उनसे नगर निगम के विशेष सम्मेलन में शामिल न होने और विवाद को लेकर दिए गए बयानों पर जवाब मांगा गया।

यह विवाद उस समय सामने आया था जब नगर निगम परिषद की बैठक में कांग्रेस की दो महिला मुस्लिम पार्षदों ने वंदे मातरम् गाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने भाजपा पार्षदों को चुनौती भी दी, जिससे मामला और गरमा गया। घटना के बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने स्पष्ट कहा था कि वंदे मातरम् सभी को गाना चाहिए। इस बयान के बाद पार्टी के भीतर मतभेद खुलकर सामने

आए और संगठन दो हिस्सों में बंटा दिखाई दिया। विवाद बढ़ने पर दोनों महिला पार्षद फौजिया अलीम और रुबीना खान का कहना था कि इस्लाम में मातरम् शब्द कहने की अनुमति नहीं है। इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए शहर कांग्रेस ने दोनों पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव प्रेश कांग्रेस कमेटी को भेजा था। मामले की जांच के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हरीश चौधरी ने एक समिति का गठन किया।

यह समिति अनुशासन समिति के रूप में काम कर रही है। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव संजय दत्त और उषा नायडू को शामिल किया गया है। देवास में हुई इस बैठक में नेताओं और पार्षदों से पूरे घटनाक्रम पर चिंटू चौकसे ने स्पष्ट कहा था कि वंदे मातरम् सभी को गाना चाहिए। इस बयान के बाद पार्टी के भीतर मतभेद खुलकर सामने

इंदौर-जयपुर रेल के सेकंड एसी में गंदगी, महिला यात्री ने हंगामा किया

कॉकरोच, खटमल से परेशान यात्री, शिकायत फिर भी हल नहीं



वीडियो जारी किए महिला ने अपने दावों के समर्थन में वीडियो भी साझा किए हैं, जिनमें खटमल साफ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आने वाले कुंभ मेले का जिक्र करते हुए कहा

कि यदि व्यवस्था ऐसी ही रही तो बाहर से आने वाले यात्रियों पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। वायरल हो रहे वीडियो में डॉ जोशी यह कहते हुए नजर आ रही हैं कि शुरुआत में उन्हें कुछ असहज लगा, लेकिन ध्यान नहीं दिया। बाद में जब उन्होंने देखा तो डिब्बे में कीड़े मौजूद थे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी की यह हालत है, तो सामान्य डिब्बों की स्थिति कैसी होगी।

नकारात्मक प्रतिक्रिया

इस घटना के बाद सामाजिक माध्यम पर भी लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोगों ने इसे कर्मचारियों की लापरवाही बताया, तो कुछ ने सरकार से इस दिशा में ध्यान देने की मांग की। वहीं, जब इस मामले में रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार पांडे से जानकारी ली गई, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं है।

पांच पुलिस वालों को सोना चुराना भारी पड़ा, वारंट प्रक्रिया दोषपूर्ण

मामले की शिकायत के बाद पांचों को निलंबित कर दिया

क्या रहेंगे जांच के बिंदु

- ग्वालियर कोर्ट से निकला वारंट यहां तक कौन लाया।
- वारंट तामील करने पांचों को कब भेजा।
- कार्रवाई के दौरान टीआई को क्या जानकारी दी।
- सोना चुराया तो उसे किसके पास रखा गया।
- दरवाजा तोड़ने का वीडियो घटना के इतने दिन बाद क्यों वायरल हुआ।
- सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी से भी बयान लिए जाएंगे।

दौरान घर की तलाशी के दौरान अलमारी में लगा सोना चुरा लिया था।

पुलिसकर्मियों के कृत्य का मामला जनसुनवाई में उठा। पुलिस आयुक्त संतोष सिंह ने बताया कि घटना से विभाग की छवि धूमिल हुई है। पांच

पुलिसकर्मियों की कार्य पद्धति विभाग के अनुकूल नहीं है। पूरे मामले को गंभीरता से जांच की जाएगी, इसके लिए अलग से जांच दल गठित किया जाएगा। सम्पूर्ण मामले की जांच दो दिन में की जाएगी। इसके बाद दोषियों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा।

प्रोत्साहन राशि देने से इंकार

आवेदन में मानव संसाधन प्रमुख प्रदीप चंद्रा और उप मानव संसाधन अधिकारी शिवम गुप्ता का भी उल्लेख किया गया। पीड़िता का आरोप है कि इनकी भूमिका या तो प्रताड़ना में रही या फिर उन्होंने शिकायतों को नजरअंदाज किया। पीड़िता ने यह भी कहा कि इस्तीफा देने के बाद उन्हें एक वर्ष का लगभग दो लाख रुपए का प्रोत्साहन देने से मना कर दिया गया। वर्ष 2025 से वह बैंक, श्रम कार्यालय और 'शी-बॉक्स' पोर्टल पर लगातार शिकायत कर रही हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उन्हें जनसुनवाई का सहारा लेना पड़ा। वहीं, बैंक के उप मानव संसाधन अधिकारी शिवम गुप्ता ने कहा कि उनके पास इस प्रकार के किसी शोषण की शिकायत नहीं आई है। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रोत्साहन राशि को लेकर आवेदन मिला था, लेकिन बैंक की नीति के अनुसार पीड़िता इसके लिए पात्र नहीं थीं। अन्य आरोपों की जानकारी होने से उन्होंने इनकार किया।

संपादकीय

भारत-रूस सैन्य समझौता

पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका-इजराइल के बीच जारी संघर्ष के दौरान ही भारत और रूस के बीच 'रेलेंस' (इंडो रूस रिसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट) का लागू होना जहां भारत के लिए सुखद खबर है, वहीं पड़ोसी पाकिस्तान को इस पर जम्कूर मिच्री लगी है। इसे दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रक्षा समझौता माना जा रहा है। इसके तहत संघर्ष की स्थितियों में दोनों देश एक-दूसरे के क्षेत्र में सेना, युद्धपोत और विमान तैनात कर सकेंगे। गौरतलब है कि रूस और भारत दशकों पुराने सहयोगी रहे हैं। समझौता ऐसे समय में हुआ है, जब रूस के साथ भारत अपने रिश्ते को और बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। भारत-रूस रेलेंस समझौता बीते साल मार्चको में साइन किया गया था। इसके अंतर्गत दोनों देशों को शुरुआती पांच सालों के लिए एक-दूसरे के इलाके में एक साथ 3 हजार तक सैनिक, पांच युद्धपोत और 10 मिलिट्री विमान तैनात करने की अनुमति रहेगी और इसे आपसी सहमति से अपने आप आगे बढ़ाया जा सकता है। समझौते के मुताबिक भारत अब रूस के मुरमांस्क और सेवेरोमोर्स्क में स्थित विशाल बंदरगाहों का उपयोग कर सकेगा। वह हिंद महासागर में भारतीय नौसेना से लॉजिस्टिक्स सहयोग की उम्मीद कर रहा है। यह समझौता रूस को ईंधन भरने, मरम्मत, कलपुन और अन्य सख्यता प्रदान करेगा। साथ ही यह समझौता युद्ध और शांति दोनों ही समय में लागू रहेगा, दोनों देशों को लंबी दूरी के अभियानों में पैसे और समय की बचत करने में मदद करेगा। भारत को रूसी नौसैनिक और हवाई अड्डों तक पहुंच प्रदान करता है, जिसमें आर्कटिक क्षेत्र भी शामिल है, और रूस को भारतीय सुविधाओं तक व्यापक पहुंच की अनुमति देता है। इस समझौते की पहल आठ साल से हो रही थी। लेकिन किन्हीं कारणों से इसमें देरी होती गई। अब यह समझौता जनवरी 2026 से लागू हो चुका है, हालांकि लोगों को इसकी जानकारी अब हुई है।

भारत-रूस पारस्परिक लॉजिस्टिक्स विनिमय समझौते में संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण और मानवीय मिशन भी शामिल हैं। इस समझौते का पश्चिम एशिया संघर्ष और यूक्रेन युद्ध के बीच गहरा महत्व है, न केवल सैन्य कर्मियों और उपकरणों की तैनाती को नियंत्रित करता है, बल्कि लॉजिस्टिक्स (साजो-सामान) का प्रबंधन भी करता है। साथ ही यह समझौता विशेष रूप से सैन्य टुकड़ियों की तैनाती को कवर करता है, जिससे संयुक्त प्रशिक्षण, आपदा रहित और संयुक्त अभियानों की अनुमति मिलेगी है। भारत की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव और संघर्ष की आशंकाओं के बीच यह समझौता बहुत कुछ मायने रखता है। यह अमेरिका और चीन के लिए भी चेतावनी है। इस समझौते से हमारा पड़ोसी पाकिस्तान खासा परेशान है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट डॉ. अतिया अली कायमी ने रूस-भारत समझौते पर खोज निकालते हुए कहा है कि मार्फको गलती कर रहा है। अतिया का कहना है कि अमेरिका ने भारत पर दांव लगाया और उसके संबंध बेहतर किए लेकिन आज वह अपना रख बदल रहा है। अब शायद रूस को भारत के बारे में धोखा हो गया है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का कहना है कि इस क्षेत्र में आने वाली शक्ति चक्र बनेगा ना कि भारत या अन्य कोई देश ताकतवर होगा। इस समझौते को अतिया कायमी ने एशिया की रणनीतिक हेंजिंग (जोखिम सुरक्षा उपाय) कहा है। वैसे पाकिस्तान क्या सोचता है, यह भारत की चिंता का विषय नहीं है। हमें अपने सुरक्षा हितों की तरफ ध्यान देना होगा। भारत ने अमेरिका से पीगे बढ़ाकर देख लिया। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा अस्थिर दिमाग का और बड़बोलो राष्ट्रपति होगा तो अमेरिका पर स्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जबकि रूस आज भी हमारा सबसे भरोसेमंद साथी है। यह समझौता भी इसी की पुष्टि है।

नजरिया

अजय कुमार

लेखक लखनऊ निवासी वरिष्ठ पत्रकार हैं।



युवावी साल में उत्तर प्रदेश की सियासत में रणनीतिक हलचल तेज होती जा रही हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की घड़ौ सिर पर आ रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की ताकत को मजबूत करने के लिए कैबिनेट विस्तार की तैयारी में जुटे हैं। खास बात यह है कि इस विस्तार का केंद्र बिंदु महिला वोटों को खुश करना हो सकता है। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक के गिरने के बाद भाजपा ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विरोधी दलों पर महिला विरोधी होने का ऐसा तंज कसा है कि पूरा माहौल बन गया है। इसी माहौल का फायदा उठाते हुए योगी सरकार कैबिनेट में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर मसदाताओं का दिल जीतने की कोशिश कर सकती है। न केवल महिलाएं, बल्कि ब्राह्मण, पिछड़ी जाति और दलित वोटों को भी रिझाने के लिए इन वर्गों को अधिक प्रतिनिधित्व देकर सियासी समीकरण साधे जा सकते हैं। यह कदम चुनावी साल में सत्ताधारी दल की चतुराई का नमूना पेश करेगा।

राज्य की राजनीति हमेशा से जाति, धर्म और लिंग आधारित समीकरणों पर टिकी रही है। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर जोर दिया, लेकिन अब चुनावी दबाव में सामाजिक समावेश को प्राथमिकता मिल रही है। वर्तमान कैबिनेट में महिलाओं की संख्या सीमित है। बेबी रानी माहौर और स्वाति सिंह जैसी कुल नेता हैं, लेकिन कुल मिलाकर प्रतिनिधित्व कमजोर पड़ता है। अगर कैबिनेट का विस्तार होता है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आगरा की भाजपा सांसद डॉ. प्रोमिला कटियार या गोरखपुर की रवीना कुरेल जैसी सक्रिय महिला नेताओं को जगह मिल सकती है। पश्चिमी इलाके से मेरठ की राजकुमारी दीया या सहारनपुर की उषा सिद्धू भी दावेदार हो सकती हैं। इनमें से कई विधायक या सांसद हैं, जो जमीनी मुद्दों पर मुखर रही हैं। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भाजपा ने जो प्रचार किया, उसके जवाब में यह कदम महिलाओं को संदेश देगा कि हमारी सरकार उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

वागर्थ

योगी कैबिनेट में बढेगी आधी आबादी की हिस्सेदारी?

राज्य की राजनीति हमेशा से जाति, धर्म और लिंग आधारित समीकरणों पर टिकी रही है। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर जोर दिया, लेकिन अब चुनावी दबाव में सामाजिक समावेश को प्राथमिकता मिल रही है। वर्तमान कैबिनेट में महिलाओं की संख्या सीमित है। बेबी रानी माहौर और स्वाति सिंह जैसी कुल नेता हैं, लेकिन कुल मिलाकर प्रतिनिधित्व कमजोर पड़ता है। अगर कैबिनेट का विस्तार होता है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आगरा की भाजपा सांसद डॉ. प्रोमिला कटियार या गोरखपुर की रवीना कुरेल जैसी सक्रिय महिला नेताओं को जगह मिल सकती है। पश्चिमी इलाके से मेरठ की राजकुमारी दीया या सहारनपुर की उषा सिद्धू भी दावेदार हो सकती हैं। इनमें से कई विधायक या सांसद हैं, जो जमीनी मुद्दों पर मुखर रही हैं। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भाजपा ने जो प्रचार किया, उसके जवाब में यह कदम महिलाओं को संदेश देगा कि हमारी सरकार उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने महिला आरक्षण बिल को लेकर जो शोर मचाया, वह अब विधानसभा स्तर पर फल दे सकता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर लगाए गए महिला विरोधी ठप्पे ने विपक्ष को रक्षात्मक बना दिया है। योगी सरकार इसी मौके को भुनाने के लिए कैबिनेट में कम से कम चार-पांच नई महिला मंत्रियों को शामिल कर सकती है। इससे ग्रामीण महिलाओं से लेकर शहरी मसदाताओं तक संदेश जाएगा कि भाजपा महिलाओं के हितों की रक्षा करेगी। उदाहरण के तौर पर, बुनकर बाहुल्य इलाकों से पिछड़ी जाति की महिलाओं को जगह देकर दोहरी रणनीति अपनाई जा सकती है। अवध क्षेत्र की लक्ष्मी चौधरी या बुंदेलखंड की सुनीता सिद्धू जैसी नेता इस फॉर्मूले में फिट बैठती हैं। कैबिनेट विस्तार से न केवल संख्या बढ़ेगी, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों और जातियों का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित होगा। यह चुनावी लाभ के साथ-साथ सामाजिक संतुलन भी लाएगा।

लेकिन महिला वोटों को खुश करने की रणनीति केवल संख्या पर टिकी नहीं रहेगी। इन महिला मंत्रियों को महत्वपूर्ण विभाग सौंपे जाएंगे, जैसे महिला कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या ग्रामीण विकास। इससे साबित होगा कि यह प्रतीकात्मक कदम नहीं, बल्कि सशक्तिकरण का माध्यम है। योगी सरकार पहले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुहलक्ष्मी योजना और पिंग बस जैसी योजनाओं से महिलाओं का विश्वास जीत चुकी है। कैबिनेट विस्तार इन प्रयासों को मजबूती देगा। विपक्षी समाजवादी पार्टी पर पिता-मजूर की सियासत का आरोप लगाकर भाजपा महिलाओं को भावनात्मक रूप से जोड़ रही है। अखिलेश यादव सरकार के समय महिलाओं के प्रति उदासीनता के उदाहरणों को बार-बार उछाला जा रहा है। ऐसे में योगी का यह दांव विपक्ष को कष्टघरे में

ला खड़ा करेगा। अब बाढ़ ब्राह्मण, पिछड़ी जाति और दलित वोटों की। उत्तर प्रदेश में ये वर्ग भाजपा की कोर वोट बैंक हैं, लेकिन हालिया लोकसभा परिणामों ने सतर्क कर दिया है। ब्राह्मण समाज में अस्तोषता की खबरें आ रही हैं। वर्तमान कैबिनेट में ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व कम है। कैबिनेट विस्तार में प्रयागराज के नंद गोपाल गुप्त नंदी या कानपुर के सत्यदेव पचौरी जैसे वरिष्ठ ब्राह्मण नेताओं को जगह देकर इस गैप को भरा जा सकता है। ये नेता पार्टी के पुराने सिपाही हैं और जमीनी पकड़ रखते हैं। ब्राह्मण वोटों को यह संदेश जाएगा कि उनकी उपेक्षा नहीं हो रही। इसी तरह पिछड़ी जाति के लिए निषाद, कुशवाहा और मौर्य समुदायों से प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। आजमगढ़ के शाह आलम या बहराइच के अनिल राजभर जैसे नाम चर्चा में हैं। ये वर्ग भाजपा के लिए गढ़ों में निर्णायक साबित होते हैं।

दलित वोटों की रिझाने की चुनौती सबसे बड़ी है। बसपा की कमजोरी का फायदा उठाते हुए भाजपा ने पहले ही कई दलित नेताओं को तरजोह दी है। लेकिन कैबिनेट में आनंद स्वरूप शर्मा या बाबू सिंह कुशवाहा जैसे चेहरे जोड़कर बैंक को मजबूत किया जा सकता है। जालौन या झारसी जैसे दलित बाहुल्य क्षेत्रों से महिला दलित नेता को शामिल करना दोहरा लाभ देगा। योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व नीति ने इन वर्गों को एकजुट किया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जातिगत आकांक्षाएं भड़क रही हैं। कैबिनेट विस्तार इन्हें शांत करने का हथियार बनेगा। कुल मिलाकर 18 से 24 सदस्यों का विस्तार हो सकता है, जिसमें आठ-दस पर चेहरे महिलाओं, ब्राह्मणों, पिछड़ों और दलितों से होंगे। यह रणनीति चुनावी साल की दौरी का फायदा उठाएगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले

कैबिनेट विस्तार से नए मंत्रियों को जमीनी मुद्दों पर सक्रिय होने का मौका मिलेगा। ये विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जनसभाओं में उतरेंगे और वोटों से सीधा संवाद करेंगे। भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व भी इसकी हामी भर चुकी है। जेपी नड्डा और अमित शाह की राय में सामाजिक समावेश ही उत्तर प्रदेश फतह का राज है। विपक्षी एकता के बावजूद भाजपा का वोट शेयर मजबूत रहेगा। समाजवादी पार्टी की महापंचायतें और कांग्रेस की कोशिशें बेअसर साबित हो सकती हैं। सियासी जानकार मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की यह चाल लंबे समय तक असरदार रहेगी। 2017 और 2022 के चुनावों में भाजपा ने इसी तरह जातिगत संतुलन साधा था। अब महिला वोटों को केंद्र में रखकर नया अध्याय लिखा जा रहा है। राज्य की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी महिलाओं की है और उनका झुकाव भाजपा की ओर बढ़ा है। कैबिनेट विस्तार इसी ट्रेंड को पक्का करेगा। ब्राह्मणों का ब्राह्मण वोट, पिछड़ों का ओबीसी समर्थन और दलितों की एकजुटता मिलकर योगी सरकार को मजबूत बनाएगी। विपक्ष को अब नई रणनीति सोचनी पड़ेगी। कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हैं। लखनऊ के सियासी गलियारों में चर्चाएं जोरों पर हैं। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल की बैठकें इसी मुद्दे पर केंद्रित हो रही हैं। जल्द ही औपचारिक घोषणा हो सकती है। इससे न केवल सरकार की छवि निखरेगी, बल्कि चुनावी वेत्रणीय पार करना आसान होगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में यह कदम ऐतिहासिक साबित हो सकता है। महिलाओं को सशक्त बनाना और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना योगी मॉडल की पहचान बनेगा। विपक्ष दलों को अब सोचना होगा कि वे कैसे जवाब दें। कुल मिलाकर, यह विस्तार सत्ताधारी दल की दूरदर्शिता का प्रमाण होगा।

डिजिटल चमक में धुंधलाते शब्द: पुस्तकों का मौन संकट

विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस पर विशेष

श्वेता गोयल

लेखक शिक्षक हैं।



जानकी अचिरल धारा और मानवीय मेधा के संचित कोष का यदि कोई सजीव प्रतीक है तो वह हैं पुस्तकें। अनादि काल से मनुष्य ने अपने अनुभवों, संवेदनाओं, शोध और कल्पनाओं को शब्दों की वणमाला में पिरोकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत के रूप में सहेजकर रखा है। हालांकि आज के समय में यह प्रश्न बेहद गंभीर और चिंताजनक है कि आज के डिजिटल कोलाहल में क्या हम अपनी इस अनमोल विरासत से दूर होते जा रहे हैं? प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मानया जाने वाला 'विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस' उस सभ्यता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का क्षण है, जिसने हमें सोचने, समझने और संवाद करने की शक्ति प्रदान की। यूनेस्को द्वारा 1995 में इस दिवस की आधारशिला रखी गई थी, जिसका मूल ध्येय पुस्तकों के प्रति जनमानस में एक नवीन चेतना का संचार करना, लेखकों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करना और मुद्रित शब्दों के जादू को अक्षुण्ण बनाए रखना था किंतु वर्तमान परिदृश्य में जब हमसामाजिक ढांचे का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि पुस्तकों और पाठकों के मध्य एक अदृश्य परंतु गहरी खाई निर्मित होती जा रही है। यह विडंबना ही है कि जिस युग में सूचनाओं का अंबार लगा है, वहां ज्ञान का वास्तविक आधार 'पुस्तकें' धूल फांक रही हैं। आधुनिकता की अंधी दौड़ और तकनीक के अतिशय हस्तक्षेप ने हमारे जीवन की लय को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है। आज का मनुष्य सूचनाओं के लरित उपभोग का अभ्यस्त हो चुका है। स्मार्टफोन की नीली स्क्रीन और कंप्यूटर की स्क्रीन ने हमारी आंखों को तो व्यस्त रखा है किंतु मस्तिष्क की उर्वरता और कल्पनाशीलता को संकुचित कर दिया है। इंटरनेट से प्राप्त होने वाली जानकारीयां अक्सर खंडित और सतही होती हैं, जिन्हें हमारा मस्तिष्क एक मूकदर्शक की भांति केवल ग्रहण करता है। इसके विपरीत,

एक पुस्तक को पढ़ना केवल शब्दों को देखना नहीं बल्कि एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। पुस्तक पढ़ने के लिए जिस एकपत्रता, धैर्य और श्रम की आवश्यकता होती है, वह हमारे विचारों की धार को पैना करती है। जब हम कोई उपन्यास या गंभीर दार्शनिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमारा मस्तिष्क लेखक द्वारा सृजित दृश्यों की अपनी कल्पना से रचना करता है। यह प्रक्रिया हमारी सृजनतात्मक क्षमता को वह विस्तार देती है, जो किसी भी डिजिटल माध्यम के लिए असंभव है। टीवी और सोशल मीडिया के आभासी संसार में रचे-बसे वर्तमान समाज को आज यह समझने की आवश्यकता है कि पुस्तकों का विकल्प कोई भी यंत्र नहीं हो सकता। पुस्तकों की महत्ता केवल ज्ञानार्जन तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारी भावनाओं की संरक्षक और एकांत की सर्वश्रेष्ठ सहचरी भी हैं। जीवन के उस कठिन मोड़ पर, जब व्यक्ति स्वयं को अकेला, हाताश या उदास अनुभव करता है तो एक अच्छी पुस्तक एक सच्चे मित्र की भांति मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। पुस्तकों के भीतर जो संसार बसता है, वह हमें हमारे दुखों से बाहर निकालकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। महान अमेरिकी इतिहासकार बारबरा डब्ल्यू तुचमन ने यथार्थ ही कहा था कि पुस्तकें सभ्यता की वह वाहक हैं, जिनके बिना इतिहास मौन है, साहित्य गूंगा है और विज्ञान अंगण है। विचार और तर्क का संवाद केवल उन्हीं पत्रों पर जीवित रह सकता है, जिन्हें हम अपनी उंगलियों से स्पर्श करते हैं। यदि पुस्तकें न हों तो मनुष्य की प्रगति का कोई साक्ष्य शेष नहीं रहेगा और हमारी संस्कृतियां अपनी पहचान खो देंगी। पुस्तकें विभिन्न भाषाओं और पहचानों के मध्य एक सेतु का निर्माण करती हैं, जो हमें एक सामान्य मानवीय विरासत से जोड़ती हैं। यदि भारतीय परिरेक्ष्य में दृष्टि डालें तो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित 'विश्व पुस्तक मेला' एक सराहनीय उत्सव की भांति प्रतीत होता है। यह मेला मुद्रित दुनिया की शक्ति को पुनर्जीवित करने का एक मंच है, जहां पाठक और लेखक का प्रत्यक्ष मिलन होता है। किंतु विचाराणीय पक्ष यह है कि क्या साल में एक बार होने वाला यह भव्य आयोजन हिंदी भाषी समाज और ग्रामीण अंचलों में पुस्तकों के प्रति लालु होतें प्रेम को वापस ला सकता है? हिंदी पुस्तकों की पहुंच आज भी उस आम पाठक तक नहीं हो पा रही है, जो साहित्य का वास्तविक रसास्वादन करना चाहता है। केवल प्रदर्शनियों और मेलों से ऊपर उठकर हमें पुस्तकालय संस्कृति को पुनर्जीवित करना होगा। विश्वास्तियों और स्थानीय निकायों के पुस्तकालयों की वर्तमान दशा अत्यंतशोचनीय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में जिस समृद्ध पुस्तकालय प्रणाली और स्थानीय भाषाओं में बाल साहित्य की उपलब्धता का स्वप्न देखा गया था, वह धरातल पर अभी भी उपेक्षा का शिकार है। विशेषकर बच्चों के संदर्भ में यह स्थिति और भी

भायावह है। बाल्यकाल वह अवस्था है, जहां जिज्ञासा के अंकुर फूटते हैं। यदि इस आयु में बच्चों को प्रेरणादायक बाल साहित्य और रोचक ज्ञानवर्धक पुस्तकों से वर्चित रखा जाए तो उनका मानसिक और सामाजिक विकास अधूरा रह जाएगा। आंकड़ों के आड़ने में देखें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के स्कूलों में पुस्तकों की उपलब्धता और रखरखाव को लेकर जो उदासीनता है, वह हमारे भविष्य के प्रति एक गंभीर चूक है। लायों का बजट आवंटित होने के बावजूद यदि पुस्तकें दीमकों का आहार बन रही हैं तो यह हमारी बौद्धिक संपदा का आपराधिक अपत्य है। जब तक विद्यालय स्तर पर पुस्तकों के प्रति आकर्षण पैदा नहीं किया जाएगा, तब तक हम एक प्रबुद्ध समाज की कल्पना नहीं कर सकते। पुस्तकालय किसी भी शिक्षण संस्थान का हृदय होते हैं और यदि हृदय ही निष्प्राण हो जाए तो ज्ञान का प्रवाह स्वतः ही रुक जाएगा।

पुस्तकों के प्रति इस कम होतें लगाव का एक बड़ा कारण हमारी जीवनशैली की प्राथमिकताएं भी हैं। हम भौतिक सुख-सुविधाओं के संचय में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमने अपने घरों में 'बुकशेल्फ' के लिए स्थान बनाना छोड़ दिया है। एक समय था, जब घरों में छोटी ही सही पर एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, जिसे परिवार की प्रिथ्वी और बौद्धिक संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। आज झड़ंग रूम में विशाल टीवी तो है पर महान विचारकों की कृतियों का अभाव है। हमें समझना होगा कि अच्छे पुस्तकें युवा पीढ़ी को न केवल ज्ञानवान बनाती हैं बल्कि उनमें संस्कारों और चरित्र का निर्माण भी करती हैं। वे हमें नैतिकता की शिक्षा देती हैं और भिन्न संस्कृतियों के प्रति सहिष्णु बनाती रखिती हैं। पुस्तक एक ऐसी छिड़कनी है, जिससे बाहर झांकर हम पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन कर सकते हैं। जरूरी है कि हम डिजिटल दासता से मुक्त होकर पुनः मुद्रित अक्षरों की सुगंध की ओर लौटें। यह केवल व्यक्तिगत विकास का प्रश्न नहीं है बल्कि एक पूरी सभ्यता को बौद्धिक पतन से बचाने की चुनौती है।

जिस दिन हम अपनी संतान के हाथ में स्मार्टफोन के स्थान पर एक उत्कृष्ट पुस्तक थमा देंगे, उसी दिन से रचनात्मकता के नए क्षितिज का विस्तार आरंभ हो जाएगा। पुस्तकों के साथ हमारा संवाद ही वह अंतिम रक्षा कवच है, जो हमें इस यांत्रिक युग में 'मानव' बनाए रख सकता है। हमें संकल्प लेना होगा कि हम पुस्तकों को सजावट की वस्तु नहीं बल्कि अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। 'विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस' की सार्थकता तभी है, जब हम हर दिन कम से कम एक पृष्ठ पलें और उस शांतिपूर्ण ज्ञान का अनुभव करें, जो केवल कागज और स्याही के मेल से संभव है। साहित्य की यह मशाल बुझनी नहीं चाहिए क्योंकि इसके बुझने का अर्थ होगा, विचारों की मृत्यु और विवेक का अंत।

अर्थनीति, कूटनीति और छवि का पुनर्पाठ

अस्थिर विश्व में भारत

अरुण कुमार उनायक

लेखक समाजसेवी हैं।



वैश्विक परिदृश्य में इस्लायल, अमेरिका और ईरान के बीच फरवरी के अंत में भड़के युद्ध ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को गहरे अस्थिरता के दौर में धकेल दिया, जिससे भारत भी अप्रभावित नहीं रहा। यद्यपि सर्वदलीय बैंक में विपक्ष ने सरकार को सहयोग का आश्वासन दिया और ईरान से संवाद स्थापित कर होतपुंज जलडमरूमध्य से तेल टैंकरों की आवाजही सुनिश्चित करने में आंशिक सफलता मिली, जिससे ऊर्जा संकट को काफी हद तक शांति का सफा, फिर भी महंगाई, बेरोजगारी और शेर बाजार में आई तीव्र गिरावट ने आम नागरिकों को आर्थिक रूप से प्रभावित किया, जिसकी भरपाई में समय लगेगा। इसी कालखंड में कुछ वैश्विक घटनाएं भारत के लिए मिश्रित संकेत लेकर आईं, जो यह दर्शाती हैं कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत को अपनी कूटनीतिक रणनीति, आर्थिक सुदृढ़ता और वैश्विक भूमिका-तौरों पर गंभीर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का आरंभ एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस संदर्भ में विदेश मंत्री की ताल्कालिक प्रतिक्रिया बौद्धिक वर्ग में व्यापक स्वीकृति नहीं पा सकी। विदेश मंत्री जैसे राजनीतिक पद से स्वाभाविक रूप से अपेक्षा संवेदनशील और व्यापक दृष्टिकोण की अपेक्षा होती है। ऐसे में उनका हालिया वक्तव्य अधिक उपयुक्त किसी पेंसेवर राजनयिक के मुख से प्रतीत होता है-शायद यह कारण है कि पूर्व विदेश सचिव की उनकी प्रशासनिक दृष्टि अब भी उनके कथनों में झलकती है, जबकि मंत्री पद उससे कहीं अधिक राजनीतिक सूक्ष्मज्ञ की मांग करता है। यह स्थिति कहीं न कहीं भारत की कूटनीतिक सीमाओं को भी उजागर करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की विभिन्न वैश्विक नेताओं से निकटता के बावजूद भारत इस शांति पहल में निर्णायक भूमिका हेतु आवश्यक विश्वास और

प्रभाव अर्जित नहीं कर सका।

पिछले एक दशक में जब-जब विश्व में संघर्ष और अशांति बढ़ी, प्रधानमंत्री द्वारा 'यह युद्ध का युग नहीं है' की घोषणा तो बार-बार कही गई, किंतु उसके अंतर्मुख कोई ठोस शांति-योजना सामने नहीं आई। संयुक्त राष्ट्र में युद्धविराम प्रस्तावों पर मतदान से दूरी बनाकर भारत ने तटस्थता का संकेत देने का प्रयास किया, परंतु अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक हिस्से ने इसे निष्पक्षता के बजाय अनिर्णय के रूप में देखा। परिणामस्वरूप, जहाँ नेहरू युग में भारत कोरियाई और वियतनामी संकटों में मध्यस्थता के लिए जाना जाता था, वहीं आज उसकी वह होतपुंज जलडमरूमध्य से तेल टैंकरों की आवाजही सुनिश्चित करने में आंशिक सफलता मिली, जिससे ऊर्जा संकट को काफी हद तक शांति का सफा, फिर भी महंगाई, बेरोजगारी और शेर बाजार में आई तीव्र गिरावट ने आम नागरिकों को आर्थिक रूप से प्रभावित किया, जिसकी भरपाई में समय लगेगा। इसी कालखंड में कुछ वैश्विक घटनाएं भारत के लिए मिश्रित संकेत लेकर आईं, जो यह दर्शाती हैं कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत को अपनी कूटनीतिक रणनीति, आर्थिक सुदृढ़ता और वैश्विक भूमिका-तौरों पर गंभीर पुनर्विचार की आवश्यकता है, जब नेपाल और बांग्लादेश के अपेक्षाकृत नए नेतृत्व को इसमें स्थान मिला है। यह स्थिति भारत की उस उपरती वैश्विक छवि पर स्वाभाविक प्रश्न उठाती है, जिसे घरेलू विधार्थ में बार-बार रेखांकित किया जाता रहा है, और अंतरराष्ट्रीय मान्यता व घरेलू दावों के बीच उपरती दूरी को और संकेत करती है। इसके साथ ही वैश्विक मंत्रों की ताल्कालिक प्रतिक्रिया बौद्धिक वर्ग में व्यापक स्वीकृति नहीं पा सकी। विदेश मंत्री जैसे राजनीतिक पद से स्वाभाविक रूप से अपेक्षा संवेदनशील और व्यापक दृष्टिकोण की अपेक्षा होती है। ऐसे में उनका हालिया वक्तव्य अधिक उपयुक्त किसी पेंसेवर राजनयिक के मुख से प्रतीत होता है-शायद यह कारण है कि पूर्व विदेश सचिव की उनकी प्रशासनिक दृष्टि अब भी उनके कथनों में झलकती है, जबकि मंत्री पद उससे कहीं अधिक राजनीतिक सूक्ष्मज्ञ की मांग करता है। यह स्थिति कहीं न कहीं भारत की कूटनीतिक सीमाओं को भी उजागर करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की विभिन्न वैश्विक नेताओं से निकटता के बावजूद भारत इस शांति पहल में निर्णायक भूमिका हेतु आवश्यक विश्वास और

प्रभाव अर्जित नहीं कर सका। पिछले एक दशक में जब-जब विश्व में संघर्ष और अशांति बढ़ी, प्रधानमंत्री द्वारा 'यह युद्ध का युग नहीं है' की घोषणा तो बार-बार कही गई, किंतु उसके अंतर्मुख कोई ठोस शांति-योजना सामने नहीं आई। संयुक्त राष्ट्र में युद्धविराम प्रस्तावों पर मतदान से दूरी बनाकर भारत ने तटस्थता का संकेत देने का प्रयास किया, परंतु अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक हिस्से ने इसे निष्पक्षता के बजाय अनिर्णय के रूप में देखा। परिणामस्वरूप, जहाँ नेहरू युग में भारत कोरियाई और वियतनामी संकटों में मध्यस्थता के लिए जाना जाता था, वहीं आज उसकी वह होतपुंज जलडमरूमध्य से तेल टैंकरों की आवाजही सुनिश्चित करने में आंशिक सफलता मिली, जिससे ऊर्जा संकट को काफी हद तक शांति का सफा, फिर भी महंगाई, बेरोजगारी और शेर बाजार में आई तीव्र गिरावट ने आम नागरिकों को आर्थिक रूप से प्रभावित किया, जिसकी भरपाई में समय लगेगा। इसी कालखंड में कुछ वैश्विक घटनाएं भारत के लिए मिश्रित संकेत लेकर आईं, जो यह दर्शाती हैं कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत को अपनी कूटनीतिक रणनीति, आर्थिक सुदृढ़ता और वैश्विक भूमिका-तौरों पर गंभीर पुनर्विचार की आवश्यकता है, जब नेपाल और बांग्लादेश के अपेक्षाकृत नए नेतृत्व को इसमें स्थान मिला है। यह स्थिति भारत की उस उपरती वैश्विक छवि पर स्वाभाविक प्रश्न उठाती है, जिसे घरेलू विधार्थ में बार-बार रेखांकित किया जाता रहा है, और अंतरराष्ट्रीय मान्यता व घरेलू दावों के बीच उपरती दूरी को और संकेत करती है। इसके साथ ही वैश्विक मंत्रों की ताल्कालिक प्रतिक्रिया बौद्धिक वर्ग में व्यापक स्वीकृति नहीं पा सकी। विदेश मंत्री जैसे राजनीतिक पद से स्वाभाविक रूप से अपेक्षा संवेदनशील और व्यापक दृष्टिकोण की अपेक्षा होती है। ऐसे में उनका हालिया वक्तव्य अधिक उपयुक्त किसी पेंसेवर राजनयिक के मुख से प्रतीत होता है-शायद यह कारण है कि पूर्व विदेश सचिव की उनकी प्रशासनिक दृष्टि अब भी उनके कथनों में झलकती है, जबकि मंत्री पद उससे कहीं अधिक राजनीतिक सूक्ष्मज्ञ की मांग करता है। यह स्थिति कहीं न कहीं भारत की कूटनीतिक सीमाओं को भी उजागर करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की विभिन्न वैश्विक नेताओं से निकटता के बावजूद भारत इस शांति पहल में निर्णायक भूमिका हेतु आवश्यक विश्वास और

प्रभाव अर्जित नहीं कर सका। पिछले एक दशक में जब-जब विश्व में संघर्ष और अशांति बढ़ी, प्रधानमंत्री द्वारा 'यह युद्ध का युग नहीं है' की घोषणा तो बार-बार कही गई, किंतु उसके अंतर्मुख कोई ठोस शांति-योजना सामने नहीं आई। संयुक्त राष्ट्र में युद्धविराम प्रस्तावों पर मतदान से दूरी बनाकर भारत ने तटस्थता का संकेत देने का प्रयास किया, परंतु अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक हिस्से ने इसे निष्पक्षता के बजाय अनिर्णय के रूप में देखा। परिणामस्वरूप, जहाँ नेहरू युग में भारत कोरियाई और वियतनामी संकटों में मध्यस्थता के लिए जाना जाता था, वहीं आज उसकी वह होतपुंज जलडमरूमध्य से तेल टैंकरों की आवाजही सुनिश्चित करने में आंशिक सफलता मिली, जिससे ऊर्जा संकट को काफी हद तक शांति का सफा, फिर भी महंगाई, बेरोजगारी और शेर बाजार में आई तीव्र गिरावट ने आम नागरिकों को आर्थिक रूप से प्रभावित किया, जिसकी भरपाई में समय लगेगा। इसी कालखंड में कुछ वैश्विक घटनाएं भारत के लिए मिश्रित संकेत लेकर आईं, जो यह दर्शाती हैं कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत को अपनी कूटनीतिक रणनीति, आर्थिक सुदृढ़ता और वैश्विक भूमिका-तौरों पर गंभीर पुनर्विचार की आवश्यकता है, जब नेपाल और बांग्लादेश के अपेक्षाकृत नए नेतृत्व को इसमें स्थान मिला है। यह स्थिति भारत की उस उपरती वैश्विक छवि पर स्वाभाविक प्रश्न उठाती है, जिसे घरेलू विधार्थ में बार-बार रेखांकित किया जाता रहा है, और अंतरराष्ट्रीय मान्यता व घरेलू दावों के बीच उपरती दूरी को और संकेत करती है। इसके साथ ही वैश्विक मंत्रों की ताल्कालिक प्रतिक्रिया बौद्धिक वर्ग में व्यापक स्वीकृति नहीं पा सकी। विदेश मंत्री जैसे राजनीतिक पद से स्वाभाविक रूप से अपेक्षा संवेदनशील और व्यापक दृष्टिकोण की अपेक्षा होती है। ऐसे में उनका हालिया वक्तव्य अधिक उपयुक्त किसी पेंसेवर राजनयिक के मुख से प्रतीत होता है-शायद यह कारण है कि पूर्व विदेश सचिव की उनकी प्रशासनिक दृष्टि अब भी उनके कथनों में झलकती है, जबकि मंत्री पद उससे कहीं अधिक राजनीतिक सूक्ष्मज्ञ की मांग करता है। यह स्थिति कहीं न कहीं भारत की कूटनीतिक सीमाओं को भी उजागर करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की विभिन्न वैश्विक नेताओं से निकटता के बावजूद भारत इस शांति पहल में निर्णायक भूमिका हेतु आवश्यक विश्वास और

प्रभाव अर्जित नहीं कर सका। पिछले एक दशक में जब-जब विश्व में संघर्ष और अशांति बढ़ी, प्रधानमंत्री द्वारा 'यह युद्ध का युग नहीं है' की घोषणा तो बार-बार कही गई, किंतु उसके अंतर्मुख कोई ठोस शांति-योजना सामने नहीं आई। संयुक्त राष्ट्र में युद्धविराम प्रस्तावों पर मतदान से दूरी बनाकर भारत ने तटस्थता का संकेत देने का प्रयास किया, परंतु अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक हिस्से ने इसे निष्पक्षता के बजाय अनिर्णय के रूप में देखा। परिणामस्वरूप, जहाँ नेहरू युग में भारत कोरियाई और वियतनामी संकटों में मध्यस्थता के लिए जाना जाता था, वहीं आज उसकी वह होतपुंज जलडमरूमध्य से तेल टैंकरों की आवाजही सुनिश्चित करने में आंशिक सफलता मिली, जिससे ऊर्जा संकट को काफी हद तक शांति का सफा, फिर भी महंगाई, बेरोजगारी और शेर बाजार में आई तीव्र गिरावट ने आम नागरिकों को आर्थिक रूप से प्रभावित किया, जिसकी भरपाई में समय लगेगा। इसी कालखंड में कुछ वैश्विक घटनाएं भारत के लिए मिश्रित संकेत लेकर आईं, जो यह दर्शाती हैं कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत को अपनी कूटनीतिक रणनीति, आर्थिक सुदृढ़ता और वैश्विक भूमिका-तौरों पर गंभीर पुनर्विचार की आवश्यकता है, जब नेपाल और बांग्लादेश के अपेक्षाकृत नए नेतृत्व को इसमें स्थान मिला है। यह स्थिति भारत की उस उपरती वैश्विक छवि पर स्वाभाविक प्रश्न उठाती है, जिसे घरेलू विधार्थ में बार-बार रेखांकित किया जाता रहा है, और अंतरराष्ट्रीय मान्यता व घरेलू दावों के बीच उपरती दूरी को और संकेत करती है। इसके साथ ही वैश्विक मंत्रों की ताल्कालिक प्रतिक्रिया बौद्धिक वर्ग में व्यापक स्वीकृति नहीं पा सकी। विदेश मंत्री जैसे राजनीतिक पद से स्वाभाविक रूप से अपेक्षा संवेदनशील और व्यापक दृष्टिकोण की अपेक्षा होती है। ऐसे में उनका हालिया वक्तव्य अधिक उपयुक्त किसी पेंसेवर राजनयिक के मुख से प्रतीत होता है-शायद यह कारण है कि पूर्व विदेश सचिव की उनकी प्रशासनिक दृष्टि अब भी उनके कथनों में झलकती है, जबकि मंत्री पद उससे कहीं अधिक राजनीतिक सूक्ष्मज्ञ की मांग करता है। यह स्थिति कहीं न कहीं भारत की कूटनीतिक सीमाओं को भी उजागर करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की विभिन्न वैश्विक नेताओं से निकटता के बावजूद भारत इस शांति पहल में निर्णायक भूमिका हेतु आवश्यक विश्वास और

प्रभाव अर्जित नहीं कर सका। पिछले एक दशक में जब-जब विश्व में संघर्ष और अशांति बढ़ी, प्रधानमंत्री द्वारा 'यह युद्ध का युग नहीं है' की घोषणा तो बार-बार कही गई, किंतु उसके अंतर्मुख कोई ठोस शांति-योजना सामने नहीं आई। संयुक्त राष्ट्र में युद्धविराम प्रस्तावों पर मतदान से दूरी बनाकर भारत ने तटस्थता का संकेत देने का प्रयास किया, परंतु अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक हिस्से ने इसे निष्पक्षता के बजाय अनिर्णय के रूप में देखा। परिणामस्वरूप, जहाँ नेहरू युग में भारत कोरियाई और वियतनामी संकटों में मध्यस्थता के लिए जाना जाता था, वहीं आज उसकी वह होतपुंज जलडमरूमध्य से तेल टैंकरों की आवाजही सुनिश्चित करने में आंशिक सफलता मिली, जिससे ऊर्जा संकट को काफी हद तक शांति का सफा, फिर भी महंगाई, बेरोजगारी और शेर बाजार में आई तीव्र गिरावट ने आम नागरिकों को आर्थिक रूप से प्रभावित किया, जिसकी भरपाई में समय लगेगा। इसी कालखंड में कुछ वैश्विक घटनाएं भारत के लिए मिश्रित संकेत लेकर आईं, जो यह दर्शाती हैं कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत को अपनी कूटनीतिक रणनीति, आर्थिक सुदृढ़ता और वैश्विक भूमिका-तौरों पर गंभीर पुनर्विचार की आवश्यकता है

देश की 10 'सेफ सिटीज' में ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में मध्यप्रदेश से एकमात्र धार का चयन

धार से राजेश शर्मा

आज का दिन धार-महू संसदीय क्षेत्र खासकर आदिवासी बाहुल्य धार जिले के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। देश की 10 'सेफ सिटीज' में विशिष्ट उपलब्धि के रूप में मध्यप्रदेश से एकमात्र धार का चयन होने से, धार देश के मानचित्र पर आ गया है। 'सेफ सिटी' परियोजना के माध्यम से धार जिले को एक सुरक्षित, सशक्त और आदर्श शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के अथक प्रयास रंग लाए और धार को यह सौभाग्य मिला है।

गौरतलब है कि वर्ष 2026 के लिए देशभर के 10 प्रमुख शहरों को 'सेफ सिटीज' परियोजना के अंतर्गत चयनित किया गया है, जिनमें मध्यप्रदेश से ऐतिहासिक नगरी धार को स्थान मिला है। यह चयन धार जिले के लिए गर्व और सम्मान का विषय है, जो क्षेत्र के विकास और सुरक्षा के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के प्रयास लाए रंग, लोकसभा क्षेत्र में लिखी जा रही विकास की नई इबारत



लोकसभा क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है

धार-महू संसदीय क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद एवं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर निरंतर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही हैं। उनके सक्रिय नेतृत्व और दूरदर्शी प्रयासों के परिणामस्वरूप आज लोकसभा क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। आधारभूत संरचना से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक, हर क्षेत्र में प्रगति देखने को मिल रही है। इसी क्रम में धार जिले को एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त हुई है। केंद्रीय मंत्री के विशेष प्रयासों से केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 'निर्भया फंड' के अंतर्गत धार को 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत संकेत का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही: सावित्री ठाकुर

इस उपलब्धि पर सुबह सवेरे के संवाददाता राजेश शर्मा ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर से विशेष चर्चा की तो उन्होंने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी बाहुल्य जिलों के लिए बेहद संवेदनशील हैं और लगातार सौगात दे रहे हैं। धार जिले को भी प्रधानमंत्री मोदीजी एक से बढ़कर एक उपलब्धियां और सौगात दे रहे हैं। मेरी मांग पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशभर के 10 प्रमुख शहरों की 'सेफ सिटीज' परियोजना में धार को शामिल कर हमें बड़ी उपलब्धि दी है।

सावित्री ठाकुर जी ने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 'सेफ सिटी' परियोजना के माध्यम से धार जिले को एक सुरक्षित, सशक्त और आदर्श शहर के रूप में विकसित किया जाएगा।

चयनित स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी, स्मार्ट लाइटिंग, महिला हेल्प डेस्क, त्वरित पुलिस सहायता व्यवस्था, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ किया जाएगा

इस परियोजना के तहत धार एवं लोकसभा क्षेत्र के चयनित स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य योजना तैयार की जाएगी। आधुनिक तकनीकों जैसे सीसीटीवी निगरानी, स्मार्ट लाइटिंग, महिला हेल्प डेस्क, त्वरित पुलिस सहायता व्यवस्था तथा सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन जैसी सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके साथ ही जागरूकता अभियानों के माध्यम से समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना को भी बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित यह महत्वाकांक्षी परियोजना महिलाओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे न केवल महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास और सामाजिक सहभागिता में भी वृद्धि होगी। उपलब्धि से पूरे लोकसभा क्षेत्र को जनता में हर्ष और उत्साह का वातावरण है।

तापमान 38 डिग्री पहुंचा, 40 के पार जाने का अनुमान

बैतूल। जिले में गर्मी ने फिर तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। अल्ट्रा वायलेट (यूवी) इंडेक्स 11 दर्ज किया गया है, जो अत्यधिक खतरनाक स्तर पर है। पिछले दो दिनों में आसमान में बादल छाए रहने से गर्मी का अहसास कुछ कम हुआ था और उमस बढ़ी थी। हालांकि, बुधवार को तेज धूप और तपते सूरज के कारण खुले में निकलना मुश्किल हो गया। शाम तक तापमान के 39-40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। आर्द्रता मात्र 17 प्रतिशत रहने से मौसम शुष्क बना हुआ है। हवा की गति करीब 14 किलोमीटर प्रति घंटे रही, लेकिन इससे गर्मी में ज्यादा राहत नहीं मिल सकी।



हीट वेव जैसी स्थिति फिलहाल नहीं- मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल हीट वेव जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन लगातार बढ़ते तापमान और तेज धूप के कारण लू जैसे हालात बनने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। पिछले कुछ दिनों के तापमान

पर गौर करें तो अधिकतम तापमान लगातार बढ़ रहा है। पहले जहां यह 39.5 से 39.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया था, वहीं अब यह 38 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहते हुए फिर बढ़ने के संकेत दे रहा है। न्यूनतम तापमान भी 21.8 से बढ़कर 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे रात में भी हल्की गर्माहट बनी हुई है।

बैतूल। मुलताई में हुई आगजनी और दंगों की एक दर्दनाक कहानी सामने आई है, जिसने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। माता-पिता की मौत के बाद अब दो मूक-बधिर बेटे-नीतीश बचले और शुभम बचले-पूरी तरह से निराश्रित और असहाय हो गए हैं। इस हृदयविदारक घटना को लेकर पूर्व विधायक एवं किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुनीलम ने जिला कलेक्टर बैतूल को पत्र

पूर्व विधायक डॉ. सुनीलम ने कलेक्टर से लगाई गुहार-राहत राशि, नौकरी और पुनर्वास की मांग

लिखकर तत्काल सहायता और पुनर्वास की मांग की है। दंगों से शुरू हुई त्रासदी, मौत तक पहुंची कहानी पत्र के अनुसार, 9-10 अक्टूबर 2025 को मुलतापी में दंगाइयों द्वारा नामदेव बचले के दो ठेलों सहित 11 अन्य ठेलों और दुकानों में आगजनी और लूटपाट की गई थी। इस घटना में नामदेव बचले को करीब 65 हजार रुपए का नुकसान हुआ। इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का



पहाड़ टूट पड़ा। 19 जनवरी 2026 को पत्नी सरिता बचले का निधन हो गया। और गहरे सदमे में 18 अप्रैल 2026 को नामदेव बचले ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली अब इस चार सदस्यीय परिवार में केवल दो बेटे ही बचे हैं, जो मूक-बधिर हैं और पूरी तरह असहाय स्थिति में जीवन जीने को मजबूर हैं। मूक-बधिर बेटों की हालत बेहद दयनीय नीतीश और शुभम बचले न सिर्फ अपने माता-पिता को खो चुके हैं, बल्कि जीविकोपार्जन का कोई साधन भी उनके

पास नहीं है। नीतीश बचले ने ब्रेल लिपि के माध्यम से बीए तक शिक्षा प्राप्त की है, इसके बावजूद रोजगार के अवसर न होने से उनका भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। अब तक दर्ज नहीं हुई एफआईआर, प्रशासन पर उठे सवाल सबसे गंभीर पहलू यह है कि इतनी बड़ी आगजनी और लूटपाट की घटना के बावजूद अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इस पर भी पत्र में चिंता जताते हुए प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए हैं।

5 लाख की राहत राशि और नौकरी की मांग

डॉ. सुनीलम ने कलेक्टर से मांग की है कि पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की जाए। नीतीश बचले को शासकीय नौकरी देकर पुनर्वास किया जाए परिवार को जीविकोपार्जन के लिए नया टेला शुरू करने हेतु आर्थिक सहायता दी जाए पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि परिवार के पास संबल कार्ड और आयुष्मान कार्ड उपलब्ध हैं, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है।

प्रशासन से मानवीय हस्तक्षेप की उम्मीद पूर्व विधायक ने कलेक्टर से आग्रह किया है कि इस मामले को संवेदनशीलता से लेते हुए पीड़ित परिवार को तत्काल राहत प्रदान की जाए। साथ ही, उन्हे कलेक्टर से व्यक्तिगत रूप से परिवार से मिलकर सांत्वना देने की भी अपील की है।

निष्कर्ष- यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि प्रशासनिक संवेदनशीलता और व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल है। अब देखा होगा कि जिला प्रशासन इस मार्मिक अपील पर कितनी जल्दी और प्रभावी कार्रवाई करता है, ताकि दो असहाय बेटों को एक नई उम्मीद मिल सके।

महिला आरक्षण पर कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने छीना पुतला

पुतला दहन की कोशिश नाकाम, पुलिस ने वाटर कैनन से रोका

बैतूल। गंज क्षेत्र स्थित टॉकीज चौखंड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग उठाई गई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का पुतला जलाने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाटर कैनन



से पानी की बौछार कर पुतले को छीन लिया और स्थिति को नियंत्रित किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोनिका निरापुरे और ग्रामीण अध्यक्ष पुष्पा पंद्रमा ने किया। पार्श्व नदिनी तिवारी सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रही। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन में भाग लिया। मोनिका निरापुरे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले ही महिला आरक्षण बिल पेश कर चुकी है और इसे 2023 में पारित किया गया, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे लागू नहीं किया। उनका कहना था कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के नाम पर जनगणना और परिसंयोजन की शर्त लगाकर इसे टालने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि महिला आरक्षण को बिना किसी शर्त के जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिल सके। पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

स्कूलों का वातावरण बच्चों के लिए आकर्षक बनाया जाए: कलेक्टर डॉ. सोनवणे

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने बुधवार को प्रभात पट्टन क्षेत्र के ग्रामों के भ्रमण के दौरान प्राथमिक शाला जामुनढाना का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने हार्जरी रजिस्टर का अवलोकन कर छात्रों की उपस्थिति, पाठ्यपुस्तक वितरण एवं मिड-डे मील की व्यवस्था की जानकारी ली। स्कूल में व्यवस्थाएं संतोषजनक न मिलने पर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शासन एवं जनभागीदारी के सहयोग से स्कूलों का समग्र वातावरण बच्चों के लिए आकर्षक बनाया जाए। उन्होंने डेस्क-बेंच की पर्याप्त व्यवस्था, स्कूल भवन का रंगरोजन तथा साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही बच्चों के लिए उपलब्ध रुचिपूर्ण पुस्तकों को अलमारी में बंद रखने के बजाय व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करने और उनके अध्ययन के लिए प्रेरित करने को कहा। खेलकूद गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश भी शिक्षकों को दिए। खोइसके पश्चात कलेक्टर ने आंगनवाड़ी केंद्र



प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण का अंतिम सत्र 23 अप्रैल से

बैतूल। जनगणना 2027 का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण है। बैतूल कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के नेतृत्व और अपर कलेक्टर तथा जिला जनगणना अधिकारी श्रीमती वंदना जाट की निगरानी में 23 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 तक तीन दिवसीय प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 10 ग्रामीण चार्ज और 9 नगरीय चार्ज में आयोजित किया जाएगा। जिला योजना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी नरेन्द्र कुमार गौतम ने बताया कि जिले में आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण अंतर्गत 30 बैचों में 10 ग्रामीण चार्ज तहसील- आमला, बैतूल, भैसदेही, भीमपुर, घोड़ाडोंगरी, प्रभात पट्टन, मुलताई, शाहपुर, चिचोली एवं आठनेर में लगभग 730 प्रगणकों एवं 130 पर्यवेक्षकों एवं 09 नगरीय चार्ज क्रमशः बैतूल, आमला, मुलताई, सारनी नगर पालिका और आठनेर, घोड़ाडोंगरी, चिचोली, शाहपुर एवं भैसदेही नगर परिषद के लगभग 310 प्रगणकों और 60 पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण सम्पन्न होगा। इसमें जात हो कि 6 प्रगणकों पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त है। इस प्रकार कुल लगभग 1040 प्रगणक और 190 पर्यवेक्षक प्रशिक्षित होंगे।

64 फील्ड ट्रेनर्स के द्वारा दिया जाएगा प्रशिक्षण

उन्होंने बताया कि सभी 19 चार्ज अंतर्गत 30 बैचों में हो रहे इस प्रशिक्षण को जिले में प्रशिक्षित किए गए 64 फील्ड ट्रेनर्स देंगे। प्रशिक्षण के अंतिम दिवस हैंड्स ऑन अभ्यास भी कराएंगे। सटीक और पारदर्शी जनगणना की मजबूत नींव प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षक फील्ड में जाने से पूर्व पूर्ण रूप से दक्ष एवं प्रशिक्षित हों, जिससे जनगणना 2027 का कार्य निर्धारित समय-सीमा में, पारदर्शिता एवं उच्च गुणवत्ता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके।

कैट की बैठक संपन्न, व्यापारियों के हितों पर हुआ मंथन



बैतूल। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग की महत्वपूर्ण संभागीय बैठक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया के आतिथ्य में हरा में संपन्न हुई। इस बैठक में व्यापारियों की समस्याओं उनकी जिम्मेदारियों तथा व्यापार में प्रगति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में विशेष रूप से अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, प्रदेश प्रदेश महामंत्री राजीव खंडेलवाल, संभाग प्रभारी मंजीत सिंह साहनी, जिला अध्यक्ष बैतूल मनोज भार्गव, हरा जिला अध्यक्ष सरगम जैन मौजूद रहे। इस मौके पर बीसी भरतिया ने विशेष रूप से महिला उद्यमियों के प्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं के साथ सार्थक संवाद किया।

आंगनवाड़ी में भोजन चखकर गुणवत्ता परखी, जर्जर भवन की मरम्मत के निर्देश

का निरीक्षण कर कुपोषित बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं के पंजीयन तथा पोषण आहार वितरण की जानकारी ली। उन्होंने आंगनवाड़ी में भोजन किए जा रहे भोजन को चखकर उसकी गुणवत्ता भी परखी।

निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी भवन जर्जर स्थिति में पाए जाने तथा छत से पानी रिसाव की समस्या सामने आने पर कलेक्टर डॉ सोनवणे ने भवन की शीश्र मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनवाड़ी में शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था की भी समीक्षा की।

पानी का स्थायी स्रोत नहीं होने पर जल जीवन मिशन के तहत स्कूल और आंगनवाड़ी में जल स्रोत विकसित कर नियमित पानी आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान जनपद सीईओ आंचल पवार, तहसीलदार संजय बैरिया, तहसीलदार यशवंत पंचार, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला निगरानी श्रीमती इंदिरा महतो सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

अपर कलेक्टर वंदना जाट ने आमजनों को स्वगणना के लिये किया प्रेरित

बैतूल। जनगणना 2027 के लिए जिला बैतूल में कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशन में अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी श्रीमती वंदना जाट द्वारा अपनी प्रत्यक्ष उपस्थिति में स्थानीय स्तर पर स्वगणना की व्यापक जानकारी मय स्टॉफ प्रदाय करके अधिकतम लोगों से स्वगणना करने की अपील की गई। जिला योजना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी नरेन्द्र कुमार गौतम ने बताया कि जनगणना 2027 पूर्वत-डिजिटल जनगणना है एवं इसका आकर्षक पहलू स्वगणना सेल्फ इनुमरेशन है। मध्यप्रदेश में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्वगणना होगी। जिले में पुराने एवं नए कलेक्टर कार्यालय, बस स्टैंड के आसपास तथा स्थानीय स्तर पर स्थित कार्यालयों में जिला जनगणना कार्यालय द्वारा अभिनव डिजिटल पहलू स्व-गणना करवाई गई। इस दौरान स्टॉफ को स्व-गणना के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें स्वयं गणना करने के लिए प्रेरित किया गया।

आमजन को प्रेरित करने हेतु मार्गदर्शन- उक्त अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों के स्टाफ को स्व-गणना के लाभ, इसकी सरल प्रक्रिया एवं समय की बचत के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। साथ ही मौके पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराते हुए स्व-गणना की प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रदर्शन भी किया गया, जिससे अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। इस पहल का उद्देश्य जनगणना प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुलभ एवं प्रभावी बनाना है, साथ ही डिजिटल माध्यम के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाना भी है। स्व-गणना को प्रोत्साहित करने के लिए अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी श्रीमती वंदना जाट मय स्टॉफ द्वारा आमजन को मार्गदर्शन प्रदान किया गया, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस अभिनव डिजिटल पहल से जुड़कर स्वयं अपनी गणना सुनिश्चित कर सकें।



श्रद्धांजलि कार्यक्रम

स्व. श्री महेश पचोरी जी

अर्चत दुब के साथ रुचित किया जाता है कि हमारे पुत्रनीय स्व. श्री महेश पचोरी जी का स्वर्गवास मृत 12 अप्रैल को हो गया है, दिनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम 24 अप्रैल 2026 (रविवार) को सां 4.30 बजे रखा गया है। अंतः- ब्रह्मस्तीन आत्मा को तार्ति हेतु आपकी उपस्थिति प्रार्थना है।

शोककूल

शोक संतुष्ट

काणिका - दिनेश शर्मा, निगिषा - संजय द्विवेदी, विपारश मिश्रा, आरुषि, तुलिका, जोरव, उत्कर्ष व संजय पचोरी परिवार

शकुंतला (धर्मपत्नी), राजेंद्र, मोहन, संजय (भाई) एवं संजय परिवारजन

कार्यक्रम स्थल

श्री द्वारका लॉन, तिवारी पेट्रोल पंप के सामने, कालापारा रोड, बैतूल

सतना में अनियंत्रित होकर नहर में गिरा सरिया लदा ट्रक, तीन की दर्दनाक मौत

सतना(नप्र)। मध्यप्रदेश में सतना-रीवा नेशनल हाईवे-39 पर बुधवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। नेमुआ मोड़ के पास सरिया से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर ड्रिवाइडर तोड़ते हुए सीधे नहर में जा गिरा। इस हृदय विदारक घटना में ट्रक सवार चालक, क्लीनर और एक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रक के केबिन में फंसे शवों को निकालने के लिए पुलिस को कटर मशीन और क्रेन की मदद लेनी पड़ी है। तब जाकर सभी के शव बाहर निकाले जा सके हैं। जानकारी के अनुसार, हादसा सुबह करीब 8 बजे के आसपास हुआ। सरिया लोड कर जा रहा ट्रक जैसे ही नेमुआ मोड़ के पास पहुंचा, चालक ने संतुलन खो दिया। ट्रक ड्रिवाइडर से टकराते हुए उसे पार कर गया और गहरे ढलान के साथ नहर में जा गिरा। ट्रक इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ कि अंदर सवार तीनों लोगों को सभलने तक का मौका नहीं मिला और वे मलबे व सरियों के बीच दब गए।



कटर मशीन से काटकर निकाले गए शव - राहगीरों की सूचना पर रामपुर बघेलान थाना प्रभारी संदीप चतुर्वेदी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। ट्रक की बाँड़ी पिचक जाने के कारण शव अंदर बुरी तरह फंसे हुए थे। पुलिस ने क्रेन बुलाकर पहले ट्रक

को सीधा कराया, जिसके बाद दो शव निकाले जा सके। तीसरे शव को निकालने के लिए गैस कटर का उपयोग कर ट्रक की बाँड़ी को काटा गया। करीब 4 घंटे चले इस भारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तीनों मृतकों को बाहर निकाला जा सका।

पैहर के रहने वाले थे दो मृतक - पुलिस ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले तीन में से दो लोगों की शिनाख्त हो गई है। दोनों मृतक पैहर जिले के निवासी हैं। मृतकों की पहचान दिलीप केवट (पिता राजेश केवट), निवासी ग्राम पडोरी, पैहर, विष्णु केवट (पिता माखनलाल केवट), निवासी रामगढ़, पैहर के रूप में हुई है। तीसरे मृतक की पहचान के प्रयास जारी हैं, जो संभवतः क्लीनर या अन्य मजदूर बताया जा रहा है।

हाईवे पर लगा रहा लंबा जाम - हादसे की भयावहता को देखते हुए एडिशनल एस्पी और तहसीलदार सुजीत नांगश भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान हाईवे पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और क्रेन की मदद से खलियस्त ट्रक को हटाकर करीब 5 घंटे बाद हाईवे पर आवागमन सुचारु कराया है। पुलिस ने मार्ग कायम कर लिया है और यह जांच की जा रही है कि हादसा वाहन में तकनीकी खराबी के कारण हुआ या चालक को झपकी आने की वजह से।

शाजापुर में हाईवे पर गदर, गेहूं रिजैक्ट हुआ तो भड़के किसान

जाम में फंसे दूल्हे से बोले- 'करो जोरदार अभिनंदन'

शाजापुर (नप्र)। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के कालापीपल क्षेत्र में मंगलवार को उस समय अर्जोबगरीब स्थिति बन गई, जब अपने उपज बेचने आए किसानों का धैर्य जवाब दे गया। ग्राम खरदौनकलां स्थित श्रीराम वेयरहाउस पर सर्वेयर द्वारा गेहूं रिजैक्ट किए जाने से नाराज किसानों ने कालापीपल-कुवार स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्रालियां खड़ी कर चक्काजाम कर दिया। करीब एक घंटे तक हाईवे पर पहिए थमे रहे, लेकिन इस तनावपूर्ण माहौल के बीच किसानों का एक मजाकिया अंदाज भी देखने को मिला।

चक्काजाम में दूल्हे से ठिठोली - जाम के दौरान वहां से एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ निकल रहा था।

किसानों ने दूल्हे की गाड़ी को रोक लिया और उसे पास बुलाकर मजाकिया अंदाज में पूछा- कहां बंशीलाल जी, इतनी धूप में खड़े होकर कैसा लग रहा है? करो इनका जोरदार अभिनंदन। जब किसानों ने पूछा कि मुहूर्त तो नहीं निकल रहा, तो दूल्हे ने हंसे हुए जवाब दिया- लगन तो हो गई, अब तो बस देवी-देवताओं की पूजा करने जा रहे हैं। इस पर किसानों ने फिर चुटकी ली और माहौल खुशनुमा हो गया।

3-3 बार फेल हो रहा सैपल - किसानों का आरोप है कि उपार्जन केंद्र पर अधिकारी नमी और गुणवत्ता का हवाला देकर बार-बार गेहूं लौटा रहे हैं। एक किसान ने बताया कि तीन-तीन बार सैपल फेल होने से उन्हें बार-बार



जाए। सर्वेयर की मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी। किसान पहले ही मौसम की मांग झेल रहे हैं, ऊपर से नमी के नाम पर परेशान करना गलत है। 3 बार सैपल फेल होने का मतलब है किसान पर दोगुना अधिक बोझ।

तहसीलदार के आश्वासन पर खुला जाम - मौके पर पहुंचे तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव ने किसानों से लंबी चर्चा की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि समस्या का समाधान किया जाएगा। पुलिस (एसआई रवि भंडारी) ने बताया कि गेहूं में मिट्टी होने के कारण ग्रेडिंग की समस्या थी। बाद में समझाइश के बाद किसानों को रोड से हटाया गया और ग्रेडिंग के बाद गेहूं की तुलाई शुरू हुई।

दोस्त ने धोखा दिया, अब जीकर क्या करूं ?

● **खरगोन में किसान ने की आत्महत्या, वीडियो में दोस्त और उसके बेटे को ठहराया जिम्मेदार**

खरगोन (नप्र)। जिले के गोगावां थाना क्षेत्र के ग्राम रेहमांव में एक किसान ने कथित तौर पर अपने ही दोस्त की धोखाधड़ी से आहत होकर खेत में कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले किसान ने एक वीडियो बनाकर दोस्त और उसके बेटे पर जमीन सौदे में लाखों रुपए की धोखाधड़ी, गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामले में आरोपित पिता-पुत्र के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज कर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

जमीन के सौदे का मामला - पुलिस के अनुसार मृतक किसान सालकराम (45) पिता मोतीराम ने गांव के ही तीन भाइयों, राजू, बोंद्रे और जितेंद्र (पिता रामेश्वर गुप्ता) से 7.52 एकड़ जमीन का सौदा किया था। यह सौदा उसने अपने करीबी मित्र सुरेश यादव के नाम से किया था। बयाना राशि एक लाख रुपए सहित दस्तावेजी खर्च भी सालकराम ने ही वहन किया था। तय हुआ था कि पांच माह में पूरी राशि अदा कर रजिस्ट्री कराई जाएगी। इस सौदे की पुष्टि गवाहों ने भी की है।

रुपए लौटाने का आरोप - मृतक द्वारा बनाए गए वीडियो में उसने बताया कि उसने राजू व जितेंद्र गुप्ता को 22 लाख 7 हजार 300 रुपए तथा अपने मित्र सुरेश यादव को 45 लाख रुपए दिए थे। इसके बावजूद सुरेश ने रुपए लौटाने से इनकार कर दिया। किसान ने यह भी आरोप लगाया कि सुरेश यादव और उसके बेटे कमलेश यादव ने उसे घर बुलाकर गाली-गलौच की और उसे व उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। वीडियो में ग्राम बिलखेड़ निवासी श्याम पर भी धमकाने के आरोप लगाए गए हैं।

सीएम बोले- कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे

माफी मांगें, पीएम पर टिप्पणी निंदनीय

महिलाकार्जुन खड़गे ने कहा था- मोदी आतंकवादी की तरह, बाद में कहा- ऐसा नहीं बोला

भोपाल (नप्र)। तमिलनाडु चुनाव प्रचार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिष्कार्जुन खड़गे के पीएम मोदी को आतंकवादी कहने पर एमपी के मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है। सीएम मोहन यादव ने बयान की निंदा करते हुए खड़गे से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का इस तरह का बयान गैर-जिम्मेदाराना है, उनको अपने आचरण और व्यवहार पर विचार करना चाहिए। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस तरह की टिप्पणी निंदनीय है। मैं मांग करता हूँ कि कांग्रेस अध्यक्ष माफी मांगें और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचें।

खड़गे ने कहा था- मोदी आतंकवादी की तरह - कांग्रेस अध्यक्ष महिष्कार्जुन खड़गे ने चेन्नई में मंगलवार को पीएम मोदी को आतंकवादी कह दिया था। हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद खड़गे ने अपने बयान पर सफाई दी। खड़गे ने कहा था 'मोदी एक आतंकवादी की तरह हैं जो समानता में विश्वास नहीं रखते। उनकी पार्टी भी समानता और न्याय में विश्वास नहीं रखती।' उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी लोगों और राजनीतिक पार्टियों को डरा रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि वह आतंकवादी हैं। मेरा मतलब है कि मोदी हमेशा धमकी देते हैं।

पटवारी सुसाइड केस में एवशन

नायब तहसीलदार निलंबित

● **परिजनों का पोस्टमार्टम से इनकार, एफआईआर की मांग को लेकर विधायक भी धरने पर**

रतलाम (नप्र)। रतलाम के आलोट में पदस्थ पटवारी रविशंकर खराड़ी के सुसाइड मामले में बढ़ते विरोध के बाद कलेक्टर मिशा सिंह ने नायब तहसीलदार सविता राठौर को निलंबित कर दिया है। मंगलवार रात से ही मृतक के परिजन और पटवारी संघ नायब तहसीलदार पर केस दर्ज करने की मांग को लेकर थाने में धरने पर बैठे थे। बुधवार सुबह परिजनों ने एफआईआर दर्ज होने तक शव का पोस्टमार्टम कराने में इनकार कर दिया और मेडिकल कॉलेज में धरने पर बैठ गए। वर्तमान से रतलाम विधायक कमलेश्वर डोडियार और जयस नेहाओं के साथ परिजन अपनी मांग पर अड़े हैं, वहीं प्रशासनिक अधिकारी उन्हें लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं।

जल संरक्षण में सभी की सहभागिता हो, सबको जोड़ें : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

पानी बचाने में मध्यप्रदेश है देश में तीसरे स्थान पर

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जल बचाने में समाज की भागीदारी जरूरी है, इसीलिए प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से सब जुड़े, सभी अपना सहयोग दें, हम सबको मिल-जुलकर यह करना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पानी बचाना हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। हम सालों से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के जरिए जल संरक्षण को जल आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। यह अभियान की सफलता ही है कि हमारा मध्यप्रदेश जल संचयन के मामले में नेशनल रैंकिंग में तीसरे स्थान पर आया है। प्रदेश में जल संरक्षण के लिए लगभग 6 हजार 278 करोड़ का वित्तीय लक्ष्य तय किया गया है। विभिन्न श्रेणियों के कुल 2.44 लाख से अधिक जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्य चिन्हित कर करीब 6 हजार 236 करोड़ रुपये की लागत से जल विकास-निकास एवं विस्तार कार्य कराये

जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को मंत्रि-परिषद् की बैठक से पहले मंत्रीगण से अनौपचारिक चर्चा में यह जानकारी देकर सभी को अपने प्रभार के जिलों में इस अभियान की नियमित समीक्षा करने तथा जल संचायन के लिए आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मंत्रीगण को बीते सप्ताह में राज्य सरकार को मिली विशेष उपलब्धियों की जानकारी भी दी।

स्कूल शिक्षा में 15 अप्रैल को आया पिछले 16 साल का सर्वश्रेष्ठ परिणाम - बेटियां रहीं अक्ल - मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि 15 अप्रैल को मंत्रिपरिषद् में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ली गई कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम घोषित हुआ। हमेशा की तरह इस बार भी होनहार बेटियां अक्ल रहीं। हमारी बेटियों को बेटों से 10 प्रतिशत अधिक सफलता मिली। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि इस बार के परिणाम पिछले 16 सालों के बोर्ड परीक्षा परिणामों में सर्वश्रेष्ठ रहे। यह हमारी सरकार द्वारा शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए किए जा रहे नवाचारों और सांदीपन

विद्यालयों की सफलता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में असफल विद्यार्थियों को 'रुक जाना नहीं परीक्षा योजना' के तहत 'द्वितीय परीक्षा अवसर' भी दिया जा रहा है। द्वितीय अवसर की परीक्षाएं 7 से 25 मई तक आयोजित होंगी। एक साल में दो परीक्षाएं आयोजित कर मध्यप्रदेश सरकार ने बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों को बहुत बड़ी राहत दी है।

अमरकंटक को 'नो मूवमेंट-नो कंस्ट्रक्शन जोन' बनाने की आवश्यकता - मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रीगण को बताया कि नर्मदा माता के उद्गम स्थल अमरकंटक को धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 13 अप्रैल को अमरकंटक में ही नर्मदा समग्र मिशन की बैठक हुई। उन्होंने कहा कि यह मनोरम स्थल प्रकृति की गोद में आध्यात्मिक शांति पाने का उत्तम केंद्र है। हम इस स्थल के विकास के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। अमरकंटक को 'नो मूवमेंट एवं नो कंस्ट्रक्शन जोन' निर्धारित करने की आवश्यकता है, जिससे निर्वाचित विरासत का संरक्षण सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि हम

अमरकंटक का इकोलॉजिकल बैलेंस में रखने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ताकि मोक्षदायिनी (पापनाशिनी) नर्मदा माता की शुचिता और पवित्रता अक्षय्य बनी रहे।

संकल्प से समाधान अभियान - 99.90 प्रतिशत आवेदनों का हुआ निराकरण - मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में इसी साल 12 जनवरी से 31 मार्च तक संकल्प से समाधान अभियान चलाया गया। अभियान में सरकार को 45.69 लाख से अधिक आवेदन मिले। इनमें से 47.68 लाख प्रकरणों का समाधान करते हुए 99.90 प्रतिशत आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह अभियान नागरिकों की समस्याओं के समाधान और उनकी जरूरतों की पूर्ति की दिशा में बेहद अच्छा प्रयास साबित हुआ। इसने प्रदेश में पारदर्शी, जवाबदेह एवं जनोन्मुखी प्रशासन को और मजबूत किया है।

21 प्रतिशत से अधिक आबादी के समग्र विकास की पूरी चिंता - मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 16 अप्रैल

को राज्यस्तरीय जनजातीय उपयोगिता कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। यह कार्यशाला प्रदेश की 21 प्रतिशत से अधिक आबादी (जनजातीय वर्ग) के समग्र विकास और कल्याण की नई रूपरेखा बनाने का महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म साबित हुई। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी चिंता के साथ जनजातीय वर्ग के हितों की सुश्रुता के लिए समुचित वित्त व्यवस्थापन एवं प्रबंधन किए हैं।

ओरछा-चंदेरी के लिए शुरू हुई पीएमश्री हेल्थी पर्यटन सेवा - मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि 19 अप्रैल को भोपाल-ओरछा और चंदेरी सेक्टर के लिए पीएमश्री हेल्थी पर्यटन सेवा का शुभारंभ किया गया। हमारे एक्विपेशन सेक्टर से महाराष्ट्र सहित कई राज्य प्रेरणा ले रहे हैं। इससे न केवल पर्यटन का विकास होगा बल्कि आर्थिक एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हेल्थीकॉर्पटर का क्रियारा, टैक्सी का शुल्क 1150 रुपए और दर्शन एवं प्रसाद के लिए 350 रुपए का भुगतान करना होगा। यात्रा के लिए 6 सीटों वाले आधुनिक हेल्थीकॉर्पटर का उपयोग किया जा रहा है।

रीवा में उतरेंगे एयरबस जैसे बड़े विमान

रनवे 2300 मीटर करने 140 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण, 340 करोड़ मुआवजा मिलेगा

रीवा (नप्र)। रीवा एयरपोर्ट पर भविष्य में एयरबस (एयरबस 320) जैसे 150 से 180 सीटर बड़े विमानों की लैंडिंग कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए रनवे की लंबाई 1800 मीटर से बढ़ाकर 2300 मीटर की जाएगी और 140 एकड़ अतिरिक्त जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। वर्तमान में प्रशासन ने जमीन का सीमांकन कर रिपोर्ट भोपाल भेज दी है, वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के अनुसार अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले 830 किसानों को 340 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है।

140 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण, रिपोर्ट भोपाल भेजी - रीवा एयरपोर्ट का तेजी से विस्तार किया जा रहा है, जिसके बाद इसे 'हवाई हब' के रूप में विकसित करने की योजना है। की मौजूदगी सामान्य बात है। लेकिन इस तरह बस्तियों में घुसने की घटना पहली बार सामने आई है। इससे पहले भी कुछ दिनों पहले नजदीक के हाईवे पर तेंदुआ को देखा गया था जहां उसने एक बकरी का शिकार किया था।

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि

इस परियोजना से लगभग 830 किसान प्रभावित होंगे, जिन्हें सरकार द्वारा 340 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है। नियमित विमान सेवा शुरू होने के बाद पांच माह में रीवा में 20,000 लोगों ने हवाई सफर किया। जिससे यह बात स्पष्ट



हो गई है कि रीवा में हवाई यात्रा को लेकर काफी पोटेंशियल है। जिस वजह से सरकार ने भी रीवा एयरपोर्ट का विस्तार करने पर सहमति जताई है।

2300 मीटर होगा रनवे, अभी सिर्फ एटीआर-72 की होती है लैंडिंग - वर्तमान में रीवा एयरपोर्ट का रनवे लगभग 1800 मीटर लंबा है। यह रनवे अभी केवल एटीआर-72 जैसे छोटे विमानों के लिए ही उपयुक्त है और अब तक यहां ऐसे ही विमान संचालित होते रहे हैं।

धार के गांव में घुसा तेंदुआ, ग्रामीणों को झपट्टा मार-मारकर गिराया

चार लोग हुए घायल, रेस्क्यू में जुटी फॉरेस्ट टीम



धार (नप्र)। मध्यप्रदेश के धार जिले के धामनोद के गुजरी डेहरिया गांव में बुधवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक तेंदुआ अचानक रहियशी इलाके में घुस आया। तेंदुए ने बस्ती में मौजूद लोगों पर हमला कर दिया जिससे एक महिला सहित कई लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में डर का माहौल बन गया और लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए।

घायलों को धार जिला अस्पताल किया गया रेफर - वहाँ, घायलों को पहले गुजरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से हालत को देखते हुए सभी

उसने राह चलते लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हमले में महेश वास्केल, ग्यारसी लाल सोलंकी, काताबाई राठोड़ और विकास खवर सहित अन्य लोग घायल हुए हैं। बाद में तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की तो उसने वनकर्मीयों पर भी हमला कर दिया। इस दौरान वन रक्षक ददू सिंह भी घायल हो गए।

घायलों को धार जिला अस्पताल किया गया रेफर - वहाँ, घायलों को पहले गुजरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से हालत को देखते हुए सभी

धीरेंद्र शास्त्री बोले-नक़टा तू अपनी कंपनी लाहौर में खोल ले

● **लेंसकार्ट के तिलक-मंगलसूत्र पाबंदी पर भड़के, कहा- बेटा गड़बड़ हो गए हो तुम, सुधर जाओ**

खजुराहो (नप्र)। प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र शास्त्री ने हनुमंत कथा के दौरान लेंसकार्ट कंपनी को चेतावनी दी। उन्होंने कहा- एक कंपनी है उसका नाम लेंसकार्ट है, उसने बोला है अपनी कंपनी के वर्करो को कि हमारे यहां कोई तिलक लगा के नहीं आ सकता, मंगलसूत्र पहन के नहीं आ सकता, सिंदूर लगा के नहीं आ सकता। पं. धीरेंद्र ने कहा- ठट्टरी के बरे ! नक़टा ! तू अपनी कंपनी लाहौर में खोल ले, भारत में काहे को मर रहा है? आगि के लगे ! तेरो कक्का को भारत है का? हो ! हमारे तो बाप का भारत है। हां ! जिनको तिलक से, चंदन से, वंदन से, राम से, श्याम से, हनुमान से, बाबा बागेश्वर से दिक्कत हो, वो पतली गली लाहौर खिस्क लें। पं. धीरेंद्र की कथा 21 से 23 अप्रैल तक चलेगी। बता दें, लेंसकार्ट विवाद कंपनी द्वारा तिलक, सिंदूर और मंगलसूत्र जैसे धार्मिक प्रतीकों पर पाबंदी के दावे से जुड़ा है।

प्रदेश में 43 डिग्री तक पहुंचा पारा, भोपाल-इंदौर भी गर्म

ग्वालियर किले पर सत्राटा, गर्मी से बचाने सज्जियों पर पानी का छिड़काव कर रहे किसान

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में दिन का तापमान 42 से 43 डिग्री के करीब पहुंच गया है, वहीं रात का तापमान भी 27 डिग्री तक बना हुआ है, जिससे लोगों को दिन-रात गर्मी से राहत नहीं मिल रही। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में लू का अलटर्न जारी किया गया है। इनमें ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रतलाम, झाबुआ, धार और अलीराजपुर शामिल हैं।

ग्वालियर किले में पर्यटकों की संख्या घटी - ग्वालियर में तापमान 41 डिग्री तक पहुंच गया है। तेज गर्मी का असर पर्यटन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। ग्वालियर किला पर दिन के समय पर्यटकों की संख्या कम हो गई है और आसपास की सड़कों पर भी सत्राटा नजर आ रहा है। टीकमगढ़ में



सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाएं चल रही हैं। मंगलवार को यहाँ अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि बुधवार को इसके 42 डिग्री पर जाने का अनुमान है। भीषण गर्मी के कारण दोपहर में स्कूलों से लौटते बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खरगोन में भी तापमान 40 डिग्री के ऊपर बना

हुआ है और दोपहर 1 बजे के बाद लू जैसे हालात बनने लगते हैं। गर्मी का असर खेती पर भी पड़ रहा है। मिर्च के पौधों को बचाने के लिए किसान लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं और नेट हाउस में तापमान नियंत्रित रखने की कोशिश कर रहे हैं।

सीधी में रहा था सबसे अधिक पारा - मंगलवार को खजुराहो और नरसिंहपुर सबसे गर्म रहे। अन्य जिलों में भी तापमान 40 डिग्री के पार रहा। सीधी में 42.6 डिग्री, नौगांव में 42.5 डिग्री, रायसेन में 42.2 डिग्री, रतलाम में 42 डिग्री, नरसिंहपुर और सतना में 41.6 डिग्री, टीकमगढ़ और रीवा में 41.5 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश के प्रमुख शहरों की बात करें तो जबलपुर में 40.6 डिग्री, भोपाल में 40.2 डिग्री, इंदौर में 39.9 डिग्री, ग्वालियर में 40.2 डिग्री और उज्जैन में 40 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया।